साप्ताहिक
# शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 15 10 - 16 अप्रैल 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

इंसाफ़ का अंतहीन इंतज़ार क्यों?
पृष्ठ-6

कैसे रुकेगी भोजन की बर्बादी
पृष्ठ-7

# दिल्ली मॉड़ल के नाम पर 'आप' का पंजाब पर कब्ज़ा

## क्या केजरीवाल मोदी का विकल्प बन रहे हैं?

**अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली मॉडल का प्रचार करके पंजाब में सरकार बनाई है, उसने उनके मोदी जी का विकल्प बनने की क्षमता उजागर कर दिया है।**

अब यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि यू.पी. में ग़रीबों को मुफ्त राशन और लाभार्थियों की बदौलत भाजपा फिर से सत्ता में आई है। विपक्ष का न तो महंगाई का नारा चला और न ही बेरोज़गारी का। लेकिन भाजपा की जीत के बाद यह बात भी शीशे की तरह साफ है कि देश में महंगाई और बेरोज़गारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या विपक्ष इसे समझ रहा है? ममता बनर्जी एक बार फिर विपक्ष को एक मंच पर आने का आहवान कर रही हैं, लेकिन मुद्दा केन्द्रिय जांच एजेंसियों की धोंसपट्टी का है। शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे भी ऐसा ही राग अलाप रहे हैं। लेकिन क्या इस मामले को लेकर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ घेराबंदी की जानी चाहिए? या फिर लंबी लकीर खींचने की ज़रूरत है?

इस बात को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल न केवल समझ गए हैं, बल्कि इस पर अमल भी कि लम्बी लकीर खींचनी है। वह अपना नया वोट बैंक तैयार करने में लगे है। यह वोट बैंक है युवा का, ग़रीबों का। दिल्ली में स्टार्टअप और पंजाब में गरीबों को घर-घर राशन। केजरीवाल 'दिल्ली मॉडल' और 'पंजाब मॉडल' की तर्ज़ पर अखिल भारतीय प्रचारित प्रसारित करने में लगे हैं। प्रश्न उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने नरेन्द्र मोदी का तोड़ निकाल लिया है? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब मॉडल को गुजरात मॉडल की तर्ज़ पर अखिल भारतीय स्तर पर शो करने निकल पड़े हैं? हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि 'केजरीवाल ने ऑउट ऑफ बॉक्स आइडिया तलाश लिया है।

अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए हैं कि इस समय मोदी सरकार ऐसा नरेटिव बनाने में लगी है जिसके तहत ममता, शरद पवार, सोनिया-राहुल, के.सी. आर., उद्धव ठाकरे को भ्रष्ट घोषित करने की कोशिश हो रही है। भाजपा राष्ट्रवाद, ईमानदारी, समावेशी विकास और चोरी चकारी के ख़िलाफ़ जीरो टोलरेंस की बात करती हैं। इसमें हिन्दुत्व का तड़का अलग से लगाया जाता है। केजरीवाल भी कट्टर राष्ट्रवाद ईमानदारी और इंसानियत की बात कर रहे हैं। हिन्दुत्व की जगह इंसानियत की बात हो रही है क्योंकि केजरीवाल समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में हिन्दुत्व में इंसानियत की जीत हो सकती है।

बड़ा प्रश्न उठता है कि ममता बनर्जी जीतती है तो सीधे गोवा पहुंच जाती हैं, वहां कांग्रेस के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ती हैं, सोनिया गांधी राहुल उनके निशाने पर रहते हैं, कांग्रेस को मरी-पिटी पार्टी बताती हैं। विपक्षी दलों के साथ दिल्ली में बैठक करती हैं। उसमें खुद को विपक्ष की धुरी साबित करने की कोशिश करती हैं या यूं कहा जाए कि कांग्रेस को हाशिए पर डाल देती हैं लेकिन भतीजे अभिषेक बनर्जी पर छापे पड़ते हैं, नौ लोगों को ज़िन्दा जलाने के मसले पर सी.बी.आई. जांच की बात होती है तो ममता को कांग्रेस की याद आने लगती है। विपक्षी एकता में कांग्रेस की मौजूदगी ज़रूरी लगने लगती हैं। यही हाल शरद पवार का है। वैसे तो पवार ने कभी भी कांग्रेस को दरकिनार नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी राजनीति भतीजे अजीत पवार और सहयोगी अनिल देशमुख को बचाने के लिए हो रही है।

संदेश ऐसा जा रहा है कि जब-जब छापे पड़ते हैं तब-तब ममता को विपक्षी एकता की बात याद आती है। संदेश ऐसा जा रहा है कि तेलंगाना में मज़बूत होती भाजपा से डरे के. सी.आर. को विपक्षी एकता की कमी महसूस करने लगते है। संदेश यह भी जा रहा है कि मातोश्री की लाज बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ज़्यादा हाथ-पैर मार रहे हैं। इसका फायदा भी भाजपा उठा रही है। या यूं कहा जाए कि भाजपा सोची समझी रणनीति के तहत इन सब नेताओं को जांच एजेंसियों के ज़रिए सताने में लगी है, ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके और लगे हाथ इन्हें भ्रष्ट घोषित करने की कोशिश की जाए।

अगर ऐसा हे तो ममता प्लस नेता क्या भाजपा के जाल में उलझ तो नहीं गए? अब अनिल देशमुख ने 6 महीने टाल-मटोल की तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। जिसकी बजाय आगे बढ़कर जांच में सहयोग की बात की जाती तो जनता तक बात पहुंचती कि देखिए हम नेताओं के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं हे और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश हो रही है। मामता को भी कहना चाहिए कि मोदी सरकार बंगाल की जनता का विकास नहीं करना चाहती, इसीलिए जांच के नाम पर बेवजह के अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ किसी नई विकास योजना की घोषणा कर देनी चाहिए थी या किसी पुरानी योजना का नाम और स्वरूप बदल कर उसे नए सिरे से पेश कर दिया जाना चाहिए था।

यह काम केजरीवाल कर रहे हैं। उन्होंने एम.सी.डी. चुनाव को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि पंजाब में ग़रीब लोगों को घर-घर राशन पहुंचाया जाएगा। भोजन के अधिकार के तहत ऐसे एक करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। पहले फोन आएगा, फिर एक नफीस बैग में राशन जाएगा। ज़ाहिर है कि बैग पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर होगी, साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे।

आम आदमी पार्टी के संयोजक समझ रहे हैं कि अगर भाजपा यू.पी. में 05 किलो अनाज मुफ्त देकर चुनाव जीत सकती है तो आदमी पार्टी घर-घर राशन पहुंचा कर चुनाव क्यों नहीं जीत सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि केन्द्र की मुफ्त राशन योजना अगले 03 माह तक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह, लेकिन पंजाब में अगले 5 साल घर-घर राशन पहुंचाएंगे केजरीवाल, उससे ज़्यादा देशभर में इसे भुनाएंगे।

उधर दिल्ली में केजरीवाल युवा वोटर का नया वर्ग बनाने में लगे हैं। उन्होंनें 11वीं और 12वीं तक के स्कूली छात्रों को स्टार्टअप के मौके देने का व्यापक कार्यक्रम बनाया है। ऐसे 03 लाख युवकों से बिजनेस आइडिया मांगे गए। 51,000 आइडिया छांटे गए। ऐसे युवकों को खुद का रोज़गार तलाशने के अवसर दिए जाएंगे। ज़ाहिर है कि जब 2025 में अगले विधानसभा चुनाव होंगे तो यह वोटर पहली बार वोट डालेगा। अब यह वोटर किसे वोट देगा यह समझाने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली में वैश्व समाज के लिए सालाना बाज़ार त्यौहार, कपड़ों के बाज़ार का हब बनाना, जबकि फूड ट्रक, क्लाउड किचन के माध्यम से व्यापारियों, पर्यटन क्षेत्र के लोगों और रेस्तरां मालिकों को खुश करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके 02 फायदे हैं। एक वैश्य समाज भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है, जो अब टूट सकता है। दो, चुनावों के समय चंदा भी ज़्यादा मिल सकता है।

कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के 'संयोजक' वहां-वहां चोट कर रहे हैं जहां-जहां भाजपा को दुखे, उसे चोट का अहसास हो। उधर ममता बनर्जी पर भाजपा वहां-वहां

**अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए हैं कि इस समय मोदी सरकार ऐसा नरेटिव बनाने में लगी है जिसके तहत ममता, शरद पवार, सोनिया-राहुल, के.सी. आर., उद्धव ठाकरे को भ्रष्ट घोषित करने की कोशिश हो रही है। भाजपा राष्ट्रवाद, ईमानदारी, समावेशी विकास और चोरी चकारी के ख़िलाफ़ जीरो टोलरेंस की बात करती हैं। इसमें हिन्दुत्व का तड़का अलग से लगाया जाता है। केजरीवाल भी कट्टर राष्ट्रवाद ईमानदारी और इंसानियत की बात कर रहे हैं। हिन्दुत्व की जगह इंसानियत की बात हो रही है क्योंकि केजरीवाल समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में हिन्दुत्व में इंसानियत की जीत हो सकती है। बड़ा प्रश्न उठता है कि ममता बनर्जी जीतती है तो सीधे गोवा पहुंच जाती हैं, वहां कांग्रेस के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ती हैं, सोनिया गांधी राहुल उनके निशाने पर रहते हैं, कांग्रेस को मरी-पिटी पार्टी बताती हैं। विपक्षी दलों के साथ दिल्ली में बैठक करती हैं।**

बाक़ी पेज 11 पर

# मालदीवः नई चुनौतियों से कैसे निपट रहा भारत

महज़ पांच लाख की आबादी वाला देश मालदीव हिन्द महासागर में अपनी भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण एशियाई राजनीति के केन्द्र में आ गया है। भारत के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता के कारण सदियों से मालदीव का बेहतर संबंध रहा हे। हाल में चीनी दख़ल और वहां के विपक्ष पर बढ़ते प्रभाव के कारण मालदीव भारत के लिए नाज़ुक मसला बन गया है। वहां राष्ट्रपति इब्राहीम सोलिह भारत के नज़दीकी दोस्त हैं।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की ताज़ा मालदीव यत्रा से पहले वहां की विपक्षी पार्टियों ने अपने भारत विरोध ी अभियान के तहत बड़ी रैली का आयोजन किया था, जिस पर सालेह की सरकार ने संसद की आपात बैठक बुलाकर रोक लगा दी। वहां की संसद ने विपक्ष की रैलियों पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। दरअसल, भारतीय विदेश मंत्री का दौरा तय होते ही पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की प्रोग्रेसिव पार्टी और उसके गठबंध न दल पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने विरोध का ऐलान कर दिया था। दोनों दलों की संभावित हरकतों के मद्देनज़र मालदीव की सरकार ने 23 मार्च को संसद में आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया जिसमें विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा बताया गया और प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव में साफ कहा गया कि विपक्ष की रैली से मालदीव और भारत के रिश्तों में खटास आएगी, इस कारण मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को रैली और विरोध प्रदर्शन के अन्य आयोजनों को रोकने का आदेश दिया गया।

इस देश में वष 2005 में लोकतंत्र आया था। हिन्द महासागर के रणनीतिक क्षेत्र में आने के कारण मालदीव एक डेढ़ दशक से काफी महत्वपूर्ण हो गया है, जब से चीन ने समुद्री क्षेत्र में अतिक्रमण करना शुरू किया। यही कारण है कि पिछले 10 साल से भारत और चीन के बीच मालदीव को अपने पाले में रखने की होड़ चल रही है।

दरअसल, मालदीव में चुनाव के दौरान विदेश नीति एक प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस छोटे से देश का आर्थिक विकास, इसकी विदेश नीति पर बहुत हद तक निर्भर है। विस्तारवाद में जुटे चीन की नज़र मालदीव पर है। वह पूर्व राष्ट्रपति यामीन को भारत के ख़िलाफ़ भड़काकर रखता है हालांकि, मौजूदा सत्ताधारी दल एमडीपी भारत के समर्थन में है। 2018 के पिछले चुनाव में एमडीपी मालदीव की सत्ता में लौटा था। तब से भारत द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूती देने क दिशा में लगातार क़दम उठा रहा है। यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में उन्हें रिहा करने का फैसला दिया। उनके जेल से निकलने के बाद वहां भारत विरोधी गतिविधियों को हवा मिल रही है। 2024 में मालदीव में आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भी विपक्ष भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा है।

अतीत में जाएं तो लोकतंत्र की स्थापना के बाद मोहम्मद नशीद देश के राष्ट्रपति बने थे और भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उसे बाद चीन का प्रभाव इस छोटे से देश में बढ़ने लगा। नशीद के बाद यामीन सत्ता में आए और वे पूरी तरह से चीन के पक्षधर हो गए। नशीद सरकार में भारत की ओर से जितने भी वहां काम हो रहे थे, सबको यामीन ने रद्द कर दिया था। 2018 में यामीन की सरकार चली गई और इब्राहीम सोलिह सत्ता में आए। सोलिह को पूर्व राष्ट्रपति और भारत के दोस्त मोहम्मद नशीद की पार्टी ने भी समर्थन दिया। ❑❑

## ओपेक के रूप से गठबंधन के पक्ष में यूएई

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के ऊर्जा मंत्री ने तेल की बढ़ती कीमतों को संभालने के लिए ओपेक के रूस के साथ गठबंधन का समर्थन किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में उछाल आया है और इसकी वजह से बाज़ार को झटका लगा है तथा उपभोक्ता बाजार में कीमतों की वृद्धि हो रही है।

यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहैल अल मजरोई ने कहा कि रूस रोज़ाना एक करोड़ बैरल का तेल उत्पादन करता है और वह वैश्विक ओपेक प्लस ऊर्जा गठबंधन का अहम सदस्य है। उन्होंने कहा, 'राजनीति को अलग रख दें तो इस तेल की आज ज़रूरत है। जब तक कोई एक करोड़ बैरल तेल उत्पादन का इच्छुक नहीं होता, हमें नहीं लगता कि रूस का विकल्प हो सकता है।' सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले इस गठबंधन के पास उत्पादन बढ़ाकर तेल की कीमतों में कमी लाने की क्षमता है जो बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान और अन्य देश खाड़ी के अरब देशों से तेल उत्पादन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इनकी कीमतों में कमी लाई जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन, ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा की थी। अल मजरोई ने बताया कि ओपेक प्लस गठबंधन एक है और बना रहेगा। उन्होंने एकतरफा तरीक़े से यूएई द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के सुझाव को लागू करने से भी एक तरह से मना कर दिया। उन्होंने कहा, 'हम एक साथ हैं। और राजनीति को इस संगठन में आने की अनुमति नहीं देंगे। हम हमेशा से मानते हैं जब उत्पादन का प्रश्न आएगा तो भी हम देश के तौर पर जो भी करेंगे, उस कार्य को हमेशा राजनीति से बाहर रखना होगा।'



# महिलाओं के हाथ होगा डीटीसी बसों का स्टेयरिंग

केजरीवाल सरकार ने बुराड़ी स्थित चालक प्रशिक्षण संस्थान में भारी मोटर वाहन (एचएमवी) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत भी मौजूद थे। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं के हाथों में डीटीसी और क्लस्टर बसों का स्टेयरिंग होगा। यह कार्यक्रम परिवहन विभाग और भारत सरकार की संयुक्त पहल का एक हिस्सा है। सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में डीटीसी और कलस्टर बसें चलाने के लिए महिला ड्राइवरों को शामिल करने के लिए इस दिशा में पहल की गई। इसका उद्देश्य दिल्ली में महिलाओं को रोज़गार का अवसर मुहैया करना है।

दिल्ली सरकार ने 180 ऐसी महिला चालकों के लिए प्रशिक्षण के लिए पहले बैच की शुरुआत की है। दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डीआईएमटीएस) ने अपने सीएसआर समर्थन के तहत इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए सोसायटी फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीटयूट (एसडीटीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महिला चालकों को विशेषज्ञों द्वारा कौशल परीक्षण सहित योग्यता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें कक्षा के साथ ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस दौरान भावी महिला चालकों को कंप्यूटर की जानकारी भी दी जाएगी। पांच बैच में महिलाओं के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण होगा। मिशन परिवर्तन और महिला संचालित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं दिल्ली में महिलाओं के लिए सम्मान और अवसर और स्वरोज़गार के बड़े दरवाज़े खोलना है। कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली में प्रशिक्षित महिला एचएमवी ड्राइवरों का एक पूल बनाना और सम्मान पैदा करना है।

### महिलाओं को छूट से बढ़ेगी संख्या

दिल्ली सरकार के एनसीटी की ओर से महिला चालकों के लिए ऊंचाई मानदंड सहित न्यूनतम तीन वर्ष के एचएमवी लाइसेंस की अनिवार्यता से भी छूट दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं को वाहन तंत्र और मरम्मत, मध्यम और भारी शुल्क ड्राइविंग, यातायात शिक्षा, जनसंपर्क और लोगों के कौशल, अग्नि ख़तरों प्राथमिक चिकित्सा और वाहन रख रखा- रखाव पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने महिला चालकों से बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

कैलाश गहलौत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली पिछले कुछ सालों से परिवहन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े क़दम उठा रही हैं भर्ती नियमों में बदलाव सहित महिलाओं के लिए अनुभव और ऊंचाई पात्रता मानदंड को कम किया है। इससे हमारी नई बसें लो फ्लोर, स्वचालित और चलाना आसान होगा और आने वाले सालों में महिला चालकों की संख्या बढ़ेगी। दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाज के प्रत्येक वर्ग चाहे वह महिला हो या पुरुष, किसी भी जात बिरादरी का हो, सबको विकास की राह पर एक साथ आगे लाने के लिए कृतसंकल्प हैं। ❑❑

## दिल्ली में क़दम जमाने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए तैयार

किसी के ख्वाबों ख्याल में भी नहीं होगा कि पंजाब का 'आम आदमी' एक नई पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिला कर पंजाब में राजनीति का नया इतिहास रच देगा। 10 वर्ष पहले राजनीतिक पटल पर जन्मी, 2014 में बिना राजनीतिक आधारभूत ढांचा के संसदीय चुनावों में 04 सीट जीत कर उपस्थिति दर्ज कराने वाली 'आम आदमी पार्टी' ने 2022 में पंजाब विधानसभा में 92 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया। इसका आभास शायद परंपरागत राजनीतिक दलों को भी नहीं था। उनका आंकलन था कि यह वही 'आप' है जिसका 2017 विधान सभा चुनावों में भी बहुत शोर था होना कुछ नहीं, हंग असेंबली आएगी, चाहे तिकडमबाज़ी, जोड़-तोड़ कर सरकारी बना ही लेंगे।

चुनावी मैनिफैस्टो में किए बड़े बड़े वायदों के बलबूते हर चुनाव जीता जाए, यह ज़रूरी नहीं। चुनाव तो किसी एक मुद्दे पर ही जीता जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मुद्दे की टाइमिंग व परिस्थितियां का सुमेल ऐसा होना चाहिए जो जनमानस के सिर चढ़ कर बोले, जैसा पंजाब के इस विधानसभा चुनाव में हुआ -'वोट फार चेंज।' 70 वर्ष के परंपरागत राजनीति में त्रस्त पंजाबी कुछ नया प्रयोग करना चाहते थे, तभी तो कुछ आभास होना शुरू हो गया था कि इस बार पंजाबी बदलाव के लिए वोट करेंगे।

मुख्यमंत्री चन्नी बकरी का दूध

बाक़ी पेज 11 पर

संपादकीय

# शांति मिशन

# क्या गाँधी नाम ही है कांग्रेस की ताक़त

हाल में सम्पन्न 05 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारत की सबसे पुरानी पार्टी होने का जिसे श्रेय प्राप्त है इन चुनावों में बुरी तरह हार को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच जो विचार विमर्श हुआ उसका नतीजा यह निकला कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गांधी परिवार का आधिपत्य रहने से ही इसका भविष्य उज्जवल रह सकता है। इस मुद्दे पर पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं मगर इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि केवल गांधी परिवार की वजह से ही कांग्रेस पार्टी भयंकर चुनावी पराजयों के बावजूद एकजुट है। हमें यह स्वीकार करने से कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप की लोकतांत्रिक राजनीति में व्यक्ति पूजा का विशिष्ट स्थान रहा है जिसके चलते केवल भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लदेश से लेकर पाकिस्तान, म्यांमार व श्रीलंका तक में सत्ता पर काबिज़ रहने वाले विभिन्न दलों की कमान उन लोगों के हाथ में रही जो एक विशेष राजनैतिक नेतृत्व के वारिस रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच अपने नायकों (हीरो) को राजतंत्रीय या सामंती व्यवस्था का ही छोड़ा हुआ परिणाम (हैंगओवर) कह सकते हैं मगर लोकतांत्रिक पद्धति की यह मजबूरी तब बन जाती है जब कोई राजनेता जन अपेक्षाओं का प्रतिबिम्ब बनकर उभरता है।

आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के लोगों ने यह प्रतिबिंब पं॰ जवाहर लाल नेहरू में उसी प्रकार देखा था जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1952 के बाद भारत के प्रथम चुनावों में कांग्रेस व पं. नेहरू का कोई विरोध ही नहीं था बल्कि तब तक सात सौ के लगभग राजनैतिक दल बन चुके थे और चुनावी मैदान में कांग्रेस व पं. नेहरू को टक्कर दे रहे थे। इनमें प्रमुख नाम डॉ. अंबेडकर, डॉ. लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव, आचार्य कृपलानी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी व वीर सावरकर जैसे थे और कम्युनिस्ट पार्टी अलग से थी। मगर पं. नेहरू की लोकप्रियता के आगे इनमें से किसी की न चली मगर इसका मतलब तब यह नहीं निकाला गया कि चुनाव में परास्त राजनैतिक दलों का नेतृत्व नकारा हाथों में है अथवा जनता के बीच इसका कोई आकर्षण ही नहीं है। जबकि हक़ीक़त यह थी कि इन सभी नेताओं के पास कांग्रेस के विमर्श के विरुद्ध बहुत सशक्त और तार्किक जन विमर्श भी थे। वर्तमान संदर्भों में इस तर्क की प्रासंगिकता यह है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह अपने भीतर की विषमताओं और विसंगतियों की शिकार बन रही है उसका ठीकरा नेतृत्व पर फोड़ने की कोशिश में कुछ नेता बदली हुई ज़मीनी राजनैतिक सच्चाई का मुक़ाबला करने से घबरा रहे हैं, और सारा दोष गांधी परिवार के सदस्यों श्रीमति सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी व प्रियंका गांधी पर लगा रहे हैं। ज़रा, इनसे कोई पूछे कि जब 1996 के चुनावों से कांग्रेस पार्टी का 'प्रभुत्व काल' शुरू हुआ तो उससे उबारते हुए किस नेता ने इस पार्टी को 2004 तक आते-आते सत्तारुढ़ पार्टी बनाया?

1996 में तो पार्टी का नेतृत्व स्व. सीताराम केसरी कर रहे थे जो बहुत ही सामान्य से परिवार से आते थे और कांग्रेस सेवा दल में बैंड बजाने से शुरुआत करके इसके कोषाध्यक्ष पद तक पहुंचे थे। इसके बाद ही श्रीमति सोनिया गांधी राजनीति में सिर्फ इसलिए आयीं क्योंकि वह स्व. इंदिरा गांधी की पुत्रवधू थीं जबकि इन्दिरा जी क ही दूसरी पुत्रवधू मेनका गांधी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। सोनिया गांधी स्व. राजीव गांधी की पत्नी थीं अत: कांग्रेसियों की छत्रछाया में स्वयं को महफूज़ समझा और कांग्रेस की 'नेहरू-इंदिरा' विरासत को अपनी पूंजी बनाया। यदि ऐसा न होता तो 1998 में ही कांग्रेस बिखर जाती क्योंकि तब तक कांग्रेस से भाजपा में जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जो सबसे पहले कुमार मंगलम, स्व. इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीकी समझे जाते थे और 70 के दशक में इंदिरा मंत्रिमंडल में केबिनेट मंत्री भी थे मगर उनकी मृत्यु एक वायुयान दुर्घटना में हो गई थी लेकिन उन्हीं के पुत्र ने कांग्रेस छोड़ कर वाजपेयी मंत्रिमंडल में बिजली राज्यमंत्री की जगह पाई थी। अत: 2004 से 2014 तक श्रीमति सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस नीत मनमोहन सिंह सरकार सत्ता पर काबिज़ रही लेकिन बढ़ती आयु व कुछ बीमारी के चलते उन्होंने अपने पुत्र राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान सौंपना उचित समझा जिससे पार्टी एकजुट रह सके लेकिन बदली हुई राजनैतिक परिस्थितियों में राहुल गांधी नरेन्द्र मोदी व भाजपा का मुक़ाबला नहीं कर सके और कांग्रेस के खाते में लोकसभा की केवल 44 सीटें ही आयीं। इसके बाद 2019 के चुनाव में केवल 54 सीटें ही जीत पाई ओर उत्तर भारत में उसका प्रभाव सीमित हो गया मगर 2018 में इसने तीन राजयों मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकारें बनाई और उससे पहले 2017 में पंजाब में विजय प्राप्त की।

2017 में ही यह मणिपुर व गोवा में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी मगर सरकारें नहीं बना सकी। यह सफलता किसके खाते में कांग्रेसी डालना पसंद करेंगे? परंतु हाल में हुए चुनावों में पांच राजयों के चुनावों में यदि कांग्रेस की बुरी 'गत' बनी है तो नेतृत्व परिवर्तन से इसका परिमार्जन किस प्रकार हो सकता है? असली राजनैतिक प्रश्न तो तब भी वही रहेगा कि पार्टी किस तरह भाजपा के जन-विमर्श काम मुक़ाबला करे। इसलिए, असली दिक्क़त वैकल्पिक 'जन विमर्श' की है नेता की नहीं और जन विमर्श पार्टी के विद्वान नेता ही तय करते हैं। इसका एक बहुत ही सादा व साधारण ताज़ा उदाहरण यह बात समझने के लिए काफी है कि जब 1971 के लोकसभा चुनावों से बहुत पहले कांग्रेस पार्टी पहली बार दो भागों में बंट गई और पार्टी के सभी दिग्गज नेता स्व. कामराज समेत स्व. निजलिंगप्पा व मोरारजी देसाई की सिंडिकेटी संगठन कांग्रेस में चले गये और इंदिरा जी लगभग अकेली रह गई और उसके द्वारा किये गये बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया तो उन्होंने अपनी पार्टी के विद्वतजनों की बैठक बुलाई जिसमें उस समय के माने हुए राजनैतिक पत्रकार स्व. श्रीकांत वर्मा भी थे। स्व. वर्मा एक कागज पर यह नारा लिख कर आगे बढ़ा दिया कि 'वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा जी कहती हैं ग़रीबी हटाओ-अब आप ही चुनिये। इसे इन्दिरा जी ने तुरंत लपक लिया और पूरे देश में कांग्रेस के चुनावी पोस्टरों पर यही नारा लिखवा कर हर शहर व गांव में चस्पा करा दिया गया। बजाये नेतृत्व परिवर्तन के कांग्रेस के नेता सत्ता से अलग होने पर क्या दिमाग़ी तौर पर भी दिवालिये हो गये हैं? असली प्रश्न यही है। ❑❑



# हज़रत उमर रज़ि॰ का फौजी निज़ाम

## फौजी दफ्तर की वसअत

हज़रत उमर रज़ि॰ ने इस सिलसिले के साथ इंतज़ामात के और विभागों पर भी ध्यान दिया और एक-एक विभाग को इस क़दर संगठित कर दिया कि इस वक़्त के लिहाज़ से एक मोअजज़ा सा मालूम होता है फौजों की भर्ती का दफ्तर जिसकी इब्तिदा मुहाजरीन और अंसार से हुई थी वसीअ होते-होते तमाम अरब को मुहीत हो गया। मदीने से असफरान तक जो मक्का मुकर्रमा से दो मंज़िल इध र है जिस क़दर कबायल आबाद है एक-एक की मरदमशुमारी होकर रजिस्टर बने। बहरीन जो अरबों का इंतहाई सूबा है बल्कि अरब के जुगराफिया नवीस इसको इराक़ के ज़िलों में शुमार करते है, वहां के तमाम कबायल का दफतर तैयार किया गया, कूफा, बसरा, मूसल, फिसताते जीरा आदि में जिस क़दर अरब आबाद हो गये थे, सबके रजिस्टर तैयार किये गये, इस बेशुमार गिरोह की अलाकदरे मरातिब तनख्वाहें मुक़र्रर की गयी और अगरचे इन सबका मजमूई शुमार तारीख़ों से मालूम नहीं होता ताह करायन से पता चलता है कि कम से कम आठ दस लाख हथियारबंद आदमी थे।

## हर साल 30 हज़ार नई फौज तैयार होती थी

इब्ने सअद की रिवायत है कि हर साल 30 हज़ार नई फौज फतूहात पर भेजी जाती थी, कूफा की निस्बत अल्लामा तबरीने तसरीह की है कि वहां एक लाख आदमी लड़ने के योग्य बसाये गये थे, जिनमें से 40 हजार बाकायदा फौज थी यानि इनको बारी-बारी से और आज़रबाइजान की मुहिमात में हाज़िर रहना ज़रूरी था। यही निज़ाम था जिसकी बदौलत एक मुद्दत तक सारी दुनिया पर अरबों का रोब दोब क़ायम रहा और फतूहात का सैलाब लगातार जारी रहा, जिस क़दर इस निज़ाम में कमी होती गई, अरब की ताक़त कमज़ोर होती गई, सबसे पहले अमीर मुआविया रज़ि॰ ने इसमें तब्दीली की यानि शीरख़्वार बच्चों का वजीफा बन्द कर दिया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने और भी इसको घटाया और मोअतसिम बिल्लाह ने सिरे से फौजी दफ्तर में से अरब के नाम निकाल दिये और इसी दिन दरहक़ीक़त हुकूमत भी मुसलमानों के हाथों से निकल गई।

## फौज में अजमी, रोमी, हिन्दुस्तानी और यहूदी भी दाख़िल किये

ये एक इत्तफाकया जुमला बीच में आ गया था हम फिर हज़रत उमर रज़ि॰ के फौजी निज़ाम की ओर वापस आते हैं, हज़रत उमर रज़ि॰ ने फौजी दफतर को यहां एक वसअत थी कि अहले अज़्म भी इसमें दाख़िल किये गये यजिद गिर्द शहशाह फारस ने वैलम की क़ौम से एक मुनतखब तैयार किया था, जिसकी तादाद चार हज़ार थी और इसको जिन्द शहंशाह यानि फौज का ख़ासा कहा जाता था जो फौज कादसिया में कई मारकों के बाद इरानियों से अलग होकर इस्लाम के हलक़े में आ गई। सऊद बिन अबी वकास रज़ि॰ गवर्नर कूफा की तरफ से उनको फौज में दाख़िल कर लिया गया और कूफा में आबाद करके इनकी तंख्वाहें भी मुक़र्रर कर दी। चुनांचे इस्लामी फतूहात में इनका नाम थी बार-बार तारीख़ों में आता है, यज्द गर्द की फौज हरावल का सरदार एक बड़ा नामी अफसर था जो सियाह के लक़ब से पुकारा जाता था। 17 हिजरी में यज्दगर्द असफहान को रवाना हुआ तो सियाह के तीन सौ सवारों के साथ जिनें 70 बड़े नामी पहलवान थे, अस्तखर की ओर भेजा कि हरेक शहर में चीदा बहादुर मुनतखिब करके अबू मूसा अशअरी रज़ि॰ ने जब 20 हिजरी में सोस का मुहासरा किया तो यज्द गुर्द ने सयाह को हुक्म दिया कि चीदा रिसाले के साथ अबू मूसा अशअरी के मुक़ाबले को जाये। सोस की फतेह के बाद सयाह ने मय तमाम सरदारों के अबू मूसा रज़ि॰ से चन्द शर्तों के साथ अमन की दरख़्वास्त की। अबू मूसा गो इन शरायत पर राज़ी न थे, लेकिन कैफिअत वाक़्या से हज़रत उमर को इत्तला दी, हज़रत उमर ने लिख भेजा कि सारी शर्तें मंजूर कर ली जाये। (जारी)

# सत्य आयोग बनाओ, मैं दोषी निकला तो मुझे फाँसी पर चढ़ा दो

## डॉ॰ फारूक अब्दुल्ला

**पिछले दिनों एक फिल्म आई है 'कश्मीर फाइल्स' जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला का नाम लिए बग़ैर उनकी छवि प्रभावित करती है, इससे बेहद आहत और नाराज़ अब्दुल्ला ने घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन और समुदाय की समस्याओं के स्थायी समाधान के बारे में विस्तृत बातचीत की, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश।**

**सवाल:**- कश्मीर फाइल्स फिल्म और उसके असर के बारे में आप क्या सोचते हैं?

**जवाब:**- यह प्रोपेगंडा मूवी है। इसने 1990 की त्रासदी को उधेड़ दिया। उस त्रासदी को, जिसने राज्य के हर व्यक्ति को प्रभावित किया, न केवल घाटी छोड़कर चले गए हिन्दू भाईयों को, बल्कि मुस्लिम बहुसंख्यकों को भी। यह दुखद स्थिति थी जो नस्ली सफाये में दिलचस्पी रखने वाले कुछ तत्वों की वजह से पैदा हुई थी। बेशक उन्हें बेनक़ाब करने की ज़रूरत है। मगर क्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ देश में इतना प्रचार करना ज़रूरी है? जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों को छोड़ दीजिए, भारत के बाकी मुसलमान भी वह दंश झेल रहे हैं जिससे उनका कुछ लेना-देना नहीं था। यह प्रोपगेंडा मुल्क को बर्बादी की ओर ले जाएगा क्योंकि 80 फीसदी आबादी और 20 फीसदी आबादी के बीच नफ़रत विनाशकारी होगी।

**सवाल:**- तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के नाते कोई कार्रवाई नहीं करने और दरअसल ढिलाई बरतने और हालात को हाथ से निकल जाने देने के लिए फिल्म कुछ हद तक आपको दोषी ठहराती लगती है..?

**जवाब:**- मैं नहीं समझता कि यह सच है। लोग आपको तरह-तरह की कहानियां सुनाएंगे, पर सच्चाई जानने के लिए, जो बहुत कड़वी होगी, आपको एक ईमानदार, इज़्ज़तदार सेवानिवृत्ति जज की और एक सत्य आयोग बनाने की ज़रूरत है। तभी लोगों को पता चलेगा कि कौन ज़िम्मेदार है। अगर अब्दुल्ला जिम्मेदार है तो वह देश में कहीं भी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। मैं उस जांच से गुज़रने को तैयार हूं पर उन लोगों को दोष न दें जो ज़िम्मेदार नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि आयोग घाटी में सिक्खों और मुसलमानों की हत्याओं और कुपवाड़ा में कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार की ईमानदारी से जांच करे, वक़्त आ गया है कि देश सच्चाई सुनें और उसके साथ जिए।

**सवाल:**- तो कौन दोषी है?

**जवाब:**- रुबैया सईद के अपहरण (दिसंबर 1989 में) को लीजिए, मैं तब मुख्यमंत्री था और भारत सरकार की अगुआई भाजपा के समर्थन से वी.पी.सिंह कर रहे थे। उनकी रिहाई के एवज में वे पांच लोगों को छोड़ देना चाहते थे जिन्हें हमने पकड़ा था, मगर मैंने उन्हें रिहा करने से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि हमें उन दहशतगर्दों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए जो मानते हैं कि अगर रूसियों को अफग़ानिस्तान से बाहर निकाला जा सकता है तो वे भारत को कश्मीर से निकालकर बाहर फेंक सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसा न करें क्योंकि यह देश के लिए भयावह त्रासदी होगी और भविष्य में हमें सारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने नहीं सुना, इस हद तक कि मुझसे कहा गया कि अगर मैंने यह नहीं किया तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे लिखकर दो कि उनके मंत्रिमंडल ने इसके लिए कहा है क्योंकि अब जो होगा, वह भारत के ताबूत में आख़िरी कील होगी और तुम इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे।

**सवाल:**- तब क्या फिर वह घाटी में निर्णायक मोड़ था?

**जवाब:**- दूसरा (निर्णायक मोड़) उसके बाद जल्द जनवरी 1990 में राज्यपाल (जगमोहन) की नियुक्ति थी। मैंने केन्द्र सरकार के अनेक बड़े नेताओं से कहा कि उन्हें मत भेजिए क्योंकि उनकी मानसिकता बंटवारे की थी और यह ज़ख़्मों को भरने की मानसिकता नहीं हो सकती थी। मैंने उनसे यह भी कहा कि वे पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं और बीच में अवरोध के तौर पर मैं था, लेकिन अगर यह बीच का (अवरोध) चला जाता है तो वे पाकिस्तान से सीधे लड़ रहें होंगे। मैंने कहा कि हम जीतेंगे पर उसके लिए मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है और अगर उन्होंने उन्हें नियुक्ति किया तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, जब उन्होंने जगमोहन की नियुक्ति की तो मैंने इस्तीफा दिया और चला गया, राज्यपाल शासन के पहले ही दिन डाउनटाउन श्रीनगर में 30 लोग मार दिए, गए फिर पंडितों को बसों में भर-भरकर घाटी से निकाल दिया गया, राज्यपाल के (आदेश पर) जिन्होंने उनसे कहा कि वे ताक़त के बल पर इन उपद्रवियों को ख़त्म कर देंगे। मगर फिर वे बदले की कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि पंडित यहां से चले जाएं और सब कुछ ठीक- ठाक होने पर वे उन्हें वापस ले आएंगे। 32 वर्ष हो चुके हैं क्या पंडित लौटे? अब वे कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ज़िम्मेदार हैं। फारूक अब्दुल्ला था कहां? दिल्ली में तुम्हारी सरकार थी और यहां तुम्हारा राज्यपाल था।

**सवाल:**- कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ हमलों में जेकेएलएफ की कथित भागीदारी के बावजूद आपकी राय में यासीन मलिक और बिट्टा कराटे पर अभी तक मुकदमा क्यों नहीं चला?

**जवाब:**- बिट्टा कराटे को क्या नेशनल कांफ्रेंस ने रिहा किया या भारत सरकार ने किया? और उन्होंने उसे किस आधार पर रिहा किया? और उन्होंने उसे किस आधार पर रिहा किया? फिर जब आइसी 814 अपहरण करके कंधार ले जाया गया (दिसंबर 1999 में) तो यात्रियों को रिहा करवाने की खाति मौलाना मसूद अज़हर और दो अन्य को लेकर कौन गया? मैंने उनसे कहा कि वे उनके खेल के आगे हथियार डाल रहे हैं मैंने उनसे गुज़ारिश की कि ऐसा न करें और कहा कि यह देश के बड़ा ख़तरा और त्रासदी होगी, पर उन्होंने नहीं सुना।

**सवाल:**- 2008 से 2014 के बीच सत्ता में होने पर आपकी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया?

**जवाब:**- मनमोहन सिंह जी की बदौलत जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, हमारी सरकार कश्मीरी पंडितों को 3,000 से ज़्यादा नौकरियां दे सकी जो उनके लिए बनाई गई थी। हमने ट्रांजिट अकॉमोडेशन बनाकर उनके परिवार को घाटी में वापस लाने के बारे में सोचा, ताकि वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा सके। दूसरी चीज़ हमने यह की कि उनका वज़ीफा, उनका राशन बढ़ाया और जहां भी वे थे, उन्हें हर तरह की राहत पहुंचाई। क्या मोदी सरकार ने सत्ता में रहते हुए इन तकरीबन आठ सालों में अब तक इनमें से कुछ भी किया? मैं यह स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा कि हमने सब कुछ नहीं किया, यह परेशानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, मगर हमने हालात को इससे बदतर तो नहीं बनाया।

**सवाल:**- मोदी सरकार यह दलील दे सकती है कि उसने अनुच्छेद 370 ख़त्म करके घाटी को पंडितों की वापसी के लिए ज़्यादा महफूज़ बनाया है?

**जवाब:**- हाल में केमिस्ट (माखन लाल) बिन्दू की हत्या के नतीजतन वापस आया हरेक हिन्दू कर्मचारी रातोरात भागकर जम्मू लौट गया। आर्टिकल 370 के ख़ात्मे से क्या यह हासिल हुआ? इस फौज के बल पर जो यहां उनके पास है, वे उन्हें भागने से रोक क्यों नहीं पाए? अगर स्थिति सामान्य होती तो क्या वे भागते? और

बाक़ी पेज 11 पर

# मेरी पार्टी में सीएम अपना टिकट भी कंफर्म नहीं मान सकता तो दूसरे के लिए क्या बोलूं : भूपेन्द्र पटेल

**05 राज्यों में चुनाव समाप्त होते ही अब सबकी नज़रें गुजरात पर हैं। गुजरात में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। भाजपा के लिए गुजरात का महत्व कोई ढंका छिपा नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती छठी बार सत्ता में वापसी करने की होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस प्रश्न का सबसे ज़्यादा तलाशा जा रहा है वह यह है कि क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन सकती है? प्रस्तुत इन मुद्दों पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से हुई एक विस्तृत बातचीत की, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश।**

**सवाल:**- चुनाव में भाजपा के लिए विशेष क्या मुद्दा होगा, ताकि फिर से वापसी कर सके?

**जवाब:**-भाजपा हर तबक़े के लोगों के लिए काम करते हैं। पेंशन योजना, फ्री राशन सहित जो भी योजनाएं हैं, वे सब तक पहुंचें, इसके लिए काम करती है। भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को बताते हैं कि उनके लिए क्या स्कीम है और सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उसका लाभ मिले।

**सवाल:**- पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, इस बार कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है?

**जवाब:**- जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तो उससे पहले ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव होता है, तो लगता नहीं कि विधानसभा चुनाव में हमें कोई दिक्क़त होगी। जो भी योजनाएं बनती हैं वे संगठन के माध्यम से नीचे तक पहुंचती हैं। सरकार और संगठन का तालमेल बहुत अच्छा रहता है इसलिए हम आत्मविश्वास से भरपूर है।

**सवाल:**- भाजपा ने कितनी सीटों का टारगेट रखा है?

**जवाब:**- मैं पाजिटिव हूं। मैंने आज तक कभी किसी को हराने की बात नहीं की है। मैं कहता हूं कि हर एक सीट हमें जीतनी है।

**सवाल:**- भाजपा ने कई राज्यों में नए लोगों पर भरोसा जताया। क्या गुजरात में भाजपा इस बार लोगों को ज़्यादा टिकट देगी?

**जवाब:**- देखिए मेरी पार्टी मैं तो मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा टिकट कंफर्म है। फिर आप तो मुझसे दूसरे के टिकट की बात कर रहे हैं..!

**सवाल:**- भाजपा लगातार छठी बार सत्ता की वापसी के लिए चुनाव मैदान में उतर रही है। एंटी इनकम्बेंसी की हर चुनाव में बात होती है, छठी बार का कितना प्रेशर है?

**जवाब:**- आप हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को देख लीजिए। जहां दूसरी बार पार्टी बदल ही जाती है वहां दूसरी बार भाजपा ही आई है। हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक को फायदा पहुंचाते हैं तब जाकर दूसरी बार आते हैं छठी बर तो और आसान हो जाएगा ना।

**सवाल:**- गुजरात में भाजपा के अलावा 'आम आदमी पार्टी' का उभार हो रहा है, आप 'आप' पार्टी को कैसे देखते है?

**जवाब:**- लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन भाजपा कभी सिर्फ इलैक्शन के समय काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम हर रोज़ काम करते हैं। भाजपा लोगों के बीच रहकर हर रोज़ काम करती है। कार्यकर्ता पब्लिक के बीच रहते हैं।

**सवाल:**- 'आप' कांग्रेस का विकल्प बन सकती है.?

**जवाब:**- अगर किसी के दिमाग़ में बैठ जाए कि विरोधी पक्ष को 4-5 या 10 सीट देनी ही है, तो वे आप को चुन सकते हैं ऐसा कहीं हो सकता है लेकिन ऐसा गुजरात में नहीं लगता।

**सवाल:**- गुजरात की या गुजरात मॉडल की बात होती है तो पीएम मोदी का ज़िक्र होता है। वह गुजरात के सीएम रहे और अब उनकी कुर्सी पर आप हैं, कितना प्रेशर फील होता है?

**जवाब:**- नरेन्द्र भाई तो एक ही हैं। उनके मार्ग दर्शन में हमें काम करना हैं नरेन्द्र भाई के जैसा काम करना तो किसी के भी बस के बात नहीं है।

**सवाल:**- गुजरात की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे आप?

**जवाब:**- मेरा काम करने का तरीक़ा ऐसा है कि बेसिक ज़रूरतों में पब्लिक को कहीं भी कुछ तकलीफ नहीं चाहिए। गुजरात की जो नीति बनाई हुई है उसमें कोई दख़लंदाज़ी करे, यह छूट किसी को नहीं है।

**सवाल:**- पाटीदार समाज की धार्मिक संस्था खोडलधाम के चेयरमैन नरेश पटेल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।

**जवाब:**- कोई भी अगर किसी पार्टी में जाना चाहेगा, तो उसे थोड़ा स्टेट्स तो चाहिए ही। अभी स्टेटस एक ही पार्टी दे सकती है वह भाजपा। तो इसके सिवा वह कहीं जाने वाले। ❑❑

# जनगणना की जटिल राह और उपाय

जनगणना 2021 में नागरिकों को गणना में शामिल होने की एक बेहतर और अनूठी ऑनलाइन सुविधा दी गई है। भारत सरकार के केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना का अधिकार देने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। जनगणना (संशोधन) 2022 के अनुसार परंपरागत तरीके से तो जनगणना घर-घर जाकर सरकारी कर्मचारी करेंगे ही, लेकिन अब नागरिक स्व-गणना के माध्यम से भी अनुसूची प्रारूप भर सकता है। इसके लिए पूर्व नियमों में 'इलेक्ट्रॉनिक फार्म' शब्द जोड़ा गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा दो की उप-धारा (एक) के खंड -आर में दिया गया है। इसके अंतर्गत मीडिया, मैग्नेटिक, कम्पयूटर जनिल माइक्रोचिप या इसी तरह के अन्य उपकरण में तैयार कर भेजी या संग्रहित की गई जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दी गई जानकारी माना जाएगा। यानि एंड्राएड मोबाईल से भी अपनी गिनती दर्ज की जा सकेगी, जो कि आजकल घर-घर में उपलब्ध हैं। इस ऑनलाइन प्रविष्टी के अलावा घर-घर जाकर भी जनगणना की जाएगी। इसके लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा दस निवेशकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। याद रहे, यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते संभव नहीं हो पाई। अब इस ऑनलाइन गणना के साथ आगे बढ़ाने की पहल की जा रही है, जिससे भारतीय नागरिकों की गिनती जल्दी से जल्द हो सके। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो संभव है 2031 की गणना पूरी तरह ऑनलाइन हो।

इसमें कोई दोराय नहीं कि ऑनलाइन प्रयोग अद्वितीय है। लेकिन देश की जनता के स्थायी और निरंतर गतिशील पंजीकरण के दृष्टिगत अब ज़रूरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंप दी जाए। गिनती के विकेन्द्रीकरण का यह नवाचार जहां दस साला जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश के पास प्रतिमाह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक व विश्वसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे। जनगणना की यह तरकीब अपनाना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ भागती यांत्रिक व कंप्यूटरीकृत ज़िन्दगी में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक बदलाव के लिए सर्वमान्य जनसंख्या के आकार व संरचना का दस साल तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। वैसे भी भारतीय समाज में जिस तेज़ी से लैंगिक, रोजगामूलक और जीवन स्तर में विषमता बढ़ रही है, उसकी बराबरी के प्रयासों के लिए भी ज़रूरी है कि हम जनगणना की परंपरा में अमूलचूल परिवर्तन लाएं।

जनसंख्या के आकार, लिंग और उसकी आयु के अनुसार उसकी जटिल संरचना का कुछ ज्ञान न हो तो आमतौर पर अर्थव्यवस्था के विकास की कालांतर में प्रगति, आमदनी में वृद्धि, खाद्य पदार्थों व पेयजल की उपलब्धता, आवास, परिवहन, संचार, रोज़गार के संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा के पर्याप्त उपायों के इजाफे के पूर्वानुमान लगा पाना मुश्किल होता है। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में ही लोकसभा और विधानसभा सीटों को परिसीमन के ज़रिए बढ़ाया जाता है। जनगणना में निरंतरता इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश व दुनिया में जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक बताई जा रही हैं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या लगभग सात सौ करोड़ हो चुकी है। 2050 में यह आंकड़ा दस अरब तक पहुंच सकता है। इस आबादी का पचास प्रतिशत से भी ज़्यादा हिस्सा महज़ नौ देशों चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, कांगो, इथोपिया और तंजानिया में होगा।

जनसंख्या वृद्धि दर का आंकलन करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में प्रतिवर्ष एक करोड़ साठ लाख आबादी बढ़ जाती है। इस दर के अनुसार हमें अपने देश की करीब एक अरब तीस करोड़ लोगों की एक निश्चित जनसंख्या प्रारूप में गिनती करनी है, ताकि व्यक्तियों और संसाधनों के समतुल्य आर्थिक व रोज़गारमूलक विकास का ख़ाका खींचा जा सके। जनसंख्या का यह आंकड़ा अज्ञात भविष्य के विकास की कसौटी पर खरा उतरे उसका मूलाधार वैज्ञानिक तरीके से की गई सटीक जनगणना ही है।

हर दस वर्ष में की जाने वाली जनता-जनार्दन की गिनती में करीब बीस लाख कर्मचारी जुटते हैं। छह लाख गांवों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के रहवासियों के द्वार-द्वार दस्तक देकर जनगणना का कार्य करना कर्मचारियों के लिए जटिल होता है। यह काम तब और बोझिल हो जाता है जब किसी कर्मचारी दल को उसके स्थानीय देनंदिन कार्य से दूर कर उसे दूरदराज़ के गांवों में भेजा जाता है। ऐसे हालात में गिनती की जल्दबाज़ी में वे मानव समूह छूट जाते हैं, जो आजीविका के लिए मूल निवास स्थल से पलायन कर चुके होते हैं। ऐसे लोगों में ज़्यादातर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लोग होते हैं। बीते कुछ सालों में आधुनिक व आर्थिक विकास की अवधारणा के चलते इन्हीं जाति समूह के करीब चार करोड़ लोग विस्थापन के दायरे में हैं। इनसे रोशन गांव तो अब बेचिराग़ हैं, लेकिन इन विस्थापितों का जनगणना के समय स्थायी ठिकाना कहां हैं, जनगणना करने आए दल को यह पता लगाना मुश्किल होता है।

इसलिए ज़रूरी है कि जनगणना की प्रक्रिया के वर्तमान स्वरूप को बदल एक ऐसे स्वरूप में तब्दील किया जाए, जिससे इसकी गिनती में निरंतरता बनी रहे। इसके लिए न भारी भरकम संस्थागत ढांचे की ज़रूरत है, न ही सरकारी अमले की। केवल गिनती केन्द्रीयकृत जटिल पद्धति को विकेन्द्रीकृत करके सरल करना है। गिनती की यह तरकीब ऊपर से शुरू न होकर नीचे से शुरू होगी। देश की सबसे छोटी राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है, जिसका त्रिस्तरीय ढांचा विकास खंड व जिला स्तर तक है। हमें करना सिर्फ इतना है कि तीन प्रतियों में एक जनसंख्या पंजी पंचायत कार्यालय में रखनी है। इसी पंजी की प्रतिलिपि कंप्यूटर में दर्ज जनसंख्या संबंधी वेबसाइट से जोड़ कर इन आंकड़ों का पंजीयन सीधे अखिल भारतीय स्तर पर हो सकता है। जैसा कि अब ऑनलाइन माध्यमों से अपनी गिनती दर्ज करा सकेंगे।

परिवार को इकाई मानकर सरपंच, सचिव और पटवारी को यह जवाबदेही सौंपी जाए कि वे परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम व अन्य जानकारियां जनसंख्या प्रारूप के अनुसार इन पंजियों में दर्ज करें। इस गिनती को सचित्र भी किया जा सकता है चूंकि ग्राम पंचायत स्तर का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, इसलिए इस गिनती में चित्र व नाम के स्तर पर भ्रम की स्थिति निर्मित नहीं होगी, जैसा कि मतदाता सूचियों और मतदाता परिचय पत्र में देखने को मिलती है। गिनती की इस प्रक्रिया से कोई वंचित भी नहीं रहेगा, क्योंकि जनगणना किए

बाक़ी पेज 11 पर

रोज़गार .....

## फार्मा इंडस्ट्री में रोज़गार के बेहतरीन विकल्प

फार्मा इंडस्ट्री में भारत का रुतबा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट से लेकर उत्पादन, क्लिनिकल ट्रायल, जेनेटिक ड्रग रिसर्च तक फैल चुका है। दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते फार्मास्युटिकल क्षेत्र को आज शानदार उद्योग में शुमार किया जाने लगा है। दवाओं के वितरण से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग, मैनेजमेंट, सभी फार्मासियुटिकल के अहम हिस्से हैं। इसमें भारत की भागीदारी सबसे अहम है। अहम वजह यह है कि भारत में इस समय 23 हजार से भी अधिक रजिस्टर्ड फार्मास्युटिकल कंपनियां हैं। इस इंडस्ट्री में तकरीबन दो लाख लोगों को काम मिला हुआ है। फार्मा इंडस्ट्री की वर्तमान प्रगति को देखते हुए अगले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री को दो से तीन गुना स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी।

विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय फार्मा उद्योग 12-13 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक इस उद्योग में तीन गुणा बढ़ोत्तरी होगी। ये तो रिपोर्ट है। वैसे भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है, जिसमें निर्यात भी शामिल है। वर्ष 2005 में देश की फार्मा इंडस्ट्री का कुल प्रोडक्शन करीब 9 बिलियन डॉलर था, जिसके आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वाजिब वजह भी है। पिछले कुछ सालों के दौरान हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ी है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।

### कार्य प्रकृति

सामान्य उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जहां सीधे डीलर या कस्टमर से संपर्क करना होता है, वहीं दवाओं की मार्केटिंग में डाक्टर अहम कड़ी होता है। दवा की खूबियों के बारे में डाक्टरों को संतुष्ट करना ज़रूरी होता है, तभी वे इसे मरीजों के प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। इसके अलावा दुकानों में दवा की उपलब्धता का पता भी रखना होता है इन्हीं ज़रूरतों को देखते हुए फार्मा मैनेजमेंट कोर्स की शुरूआत की गई है। फार्मा मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए मैनेजमेंट के साथ दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ एवं तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। दवा कंपनियां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग आफिसर के रूप में प्रशिक्षित लोगों को ही रखना चाहती हैं। पिछले कुछ समय से मल्टीनेशनल कंपनियों के भारत में आगमन से बाजार में अधिक उछाल आया है वे भारतीय कंपनियों के साथ गठजोड़ पर रास्ते प्रोडक्ट बनाने और बेचने लगी हैं। इसका असर वहां के बाजारों पर पड़ा है।

### योग्यता

100 से अधिक संस्थानों में डिग्री और 200 से अधिक संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं। फार्मा के फील्ड में अगर कैरियर बनाना है तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता है 12वीं। और न्यूनतम मार्क्स है 50 प्रतिशत । यूं तो किसी भी फैकल्टी के छात्र इस कोर्स के लिए योग्य हैं, लेकिन विज्ञान संकाय खासकर जीव विज्ञान, कैमिस्ट्री जूलोजी और बॉटनी के छात्रों के लिए फार्मा क्षेत्र में करियर बनाना आसान है। बीफार्मा और डीफार्मा के अलावा आप फार्मास्युटिकल में अनुसंधान और शोध भी कर सकते हैं।

### कौन-कौन से हैं कोर्स?

विशेषज्ञों का कहना है कि फार्मा क्षेत्र आज सर्वाधिक संभावनाओं से भरा है। मास्टर्स इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, पीजी डिप्लोमा इन फार्मास्युटिकल एवं हैल्थ केयर, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन फार्मा सेल्स एण्ड मार्केटिंग, एमबीए इन फार्मा मैनेजमेंट जैसे कोर्स हैं। इन पाठ्यक्रमों की अवधि तीन महीने से 3 वर्ष के बीच हैं।

### कहाँ-कहाँ हैं जॉब

फार्मासिस्ट:- फार्मेसी के डिग्रीधारकों को सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों के फार्मा विभाग में नौकरी मिल जाती हैं। विदेशों में भी फार्मासिस्ट की खूब डिमांड है। इसके अलावा जो खुद की फार्मास्युटिकल यूनिट शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भी डिग्री के आधार पर लाइसेंस मिल जाता है।

### रिसर्च ऑफिसर एवं साइंटिस्ट

इस फील्ड में शोध की काफी गुंजाइश है। नामी दवा कंपनियों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में वर्तमान समय में हो रहे विस्तार को देखते हुए बतौर वैज्ञानिक संभावननाओं की कमी नहीं है।

**मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव:** प्रत्येक फार्मा कंपनी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने, दवाओं के प्रचार प्रसार के लिए बड़ी संख्या में मेडिकल रिप्रजेंटेटिव एपाइंट करती है।

**मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव:** यह सामान्य उत्पादों से बिल्कुल अलग है। दवाओं की मार्केटिंग में डाक्टर अहम होता है, उन्हें संतुष्ट करना होता है। दवा की खूबियां बतानी होती हैं, तभी वे मरीजों के प्रिसक्रिप्शन में लिखते हैं। इसके अलावा दुकानों में दवा कैसे उपलब्ध हो, यह मार्केटिंग एग्जिक्यूटिव तय करता है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स एग्जिक्यूटिव, क्वालिटी कंट्रोल, को आर्डिनेटर जैसे पदों पर नियुक्त हो सकती है। खुद की दवा कंपनी या दुकान खोलकर रोज़गार शुरू किया जा सकता है।

### आमदनी

इस फील्ड में शुरुआती मासिक वेतन 20 से 25 हजार रुपये तक है। इसमें फार्मासिस्ट, थैरेपिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट एग्जिक्यूटिव पद शामिल हैं। वहीं रिसर्च और एंट्री लेवल पर सैलरी डेढ़ लाख रुपये वार्षिक मिलती है। मार्केटिंग क्षेत्र में एक फ्रेशर को 3 से 35 लाख रुपये वार्षिक मिल जाते हैं।

## इस्लामी दुनिया

### कुवैत : डेढ़ वर्ष में तीसरी सरकार ने भी दिया इस्तीफा

दुबई : कुछ ही माह पहले सत्ता संभालने वाले कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबह अल खालिद अल हमद अल सब ने शहज़ादे को मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया। राजनीतिक हालात बिगड़ने से इस छोटे से देश में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सुधार फिर रुक गए हैं।

### इमरान के अमेरिकी दख़ल के दावे से पाक सेना का इंकार

इस्लामाबाद : पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के उस बयान का खण्डन किया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने की साज़िश रचने का आरोप लगाया था। सेना ने कहा कि देश के आंतरिक मामलों में दख़ल का कोई सबूत नहीं है। इमरान ने 27 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद दावा किया था कि एक अमरिकी पत्र उनकी सरकार को गिराने के लिए लिखा गया था।

### परीक्षा से पहले ही बिकने लगी थीं कॉपियां, सोता रहा प्रशासन

यूपी बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन कराने के प्रशासनिक दावें परीक्षा से दो दिन पहले ही नकल माफिया ने तार-तार कर दिए थे। उसने नगरा क्षेत्र में डुप्लीकेट कॉपियां बेचना शुरू कर दिया था। यह ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 23 मार्च को अख़बारों में भी छपी, पर कार्रवाई न होने से नकल माफिया के हौंसले बढ़ गए और पेपर लीक करने में सफल हो गए। पांच दिन बाद प्रशासन ने दो स्टेटिक मजिस्ट्रेटी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया।

### नई सरकार के गठन तक आईएमएफ फंडिंग रुकी

पाकिस्तान में सांविधानिक संकट में बदले सियासी गतिरोध को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के वित्त पोषण से एक और झटका मिला है। इस्लामाबाद में आईएमएफ के स्थानीय प्रतिनिधि एस्तेर पेरेज रुइज ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद फंड जारी होगा। इसी के साथ पाक के लिए 6 अरब डॉलर के फंड में गतिरोध आ गया है, जबकि पीएम इमरान ख़ान ने ट्रैक्स माफी योजना और ऊर्जा कीमतों में कटौती से जुड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। पाकिस्तान में इन दिनों सत्ता संघर्ष का दौर एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है, हालात प्रत्येक दिन नई कहानियां पैदा कर रहे हैं, पाक इस संकट से कैसे ऊबर पाता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

महेन्द्र अवधेश

# इंसाफ़ का अंतहीन इंतज़ार क्यों?

विलंब से मिला न्याय किसी अन्याय से कमतर नहीं होता। सवा अरब से भी अधिक आबादी वाले हमारे देश में न्याय की प्रतिक्षा में पीढ़ियां गुज़रती जाती है, लेकिन फरियाद पर तारीखें दर्ज होने के अलावा और कुछ नहीं होता। कहीं पक्षकार को कानून की जानकारी नहीं होती, तो कहीं उसकी फटेहाली उसे न्याय पाने से वंचित कर देती हैं हाल में केन्द्र सरकार ने न्याय सबके लिए जैसे अपनी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कारगर क़दम उठाया है। इसके तहत देश के हर आमजन को विभिन्न क़ानूनों की मुकम्मल जानकारी देने और न्याय दिलाने की कवायद शुरू की गई हैं कानून मंत्रालय ने टीवी पर जागरुकता फिल्में दिखा कर आमजन को उनके कानूनी अधिकार से वाक़िफ़ कराने और न्याय की ड्योढ़ी पर पहुंचाने का संकल्प जताया है।

दरअसल, नरेन्द्र मोदी सरकार की मंशा है कि वंचित वर्ग कानून की बारीकियों को समझे, अपने अधिकारों को जाने और न्याय तक उसकी पहुंच भी सुनिश्चित हो। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग का 'डिजिटल लीगल लिटरेसी' कार्यक्रम इसी मुहिम का एक हिस्सा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वयंप्रभा परियोजना के तहत चलाए जा रहे विभिन्न शैक्षिक चैनलों में से एक चैनल पर तीस मिनट का समय कानून मंत्रालय को आबंटित किया गया है, जहां वह कानूनी जागरुकता संबंधी लघु फिल्में प्रसारित करने के साथ-साथ विशेषज्ञों की परिचर्चा भी आयोजित करेगा।

ग़ौरतलब है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विभिन्न ख़ामियां ग़रीब, बेसहारा पीड़ित पक्ष को अंतिम समय तक हलकान किए रहती है। तारीख़ पर तारीख़, समन दर समन और ऐसी तमाम कार्यवाहियां प्रक्रियाएं साधनहीन- निर्धनवादी को हतोत्साहित करती जाती है और न्याय व्यवस्था के प्रति उसका भरोसा टूटता जाता है। हर पेशी पर मुंशी, वकील, पेशकार जैसी ड्योढियां जैसे-जैसे तय होती हैं, वैसे-वैसे जेब ख़ाली होती जाती है और शाम ढले जब वादी थका हारा घर लौटता है, तो उसके पास अगली तारीख़ लिखी पर्ची और निराशा के अलावा कुछ नहीं होता।

मुक़दमा क़ायम कराने वाला अपने जीवन में उसका अंतिम फैसला देख ले, तो बड़े भाग्य की बात समझी जाती है। वरना उस मुक़दमे को पोते-पड़पोते ही निर्णीत करा पाते हैं अथवा वे भी लड़ते रहते हैं। जनवरी, 2017 में दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने पारिवारिक संपत्ति विवाद के एक मामले में अपना उल्लेखनीय फैसला सुनाया। 1968 से लंबित इस मामले में अतिरिक्त जिला जज कॉमिनी लॉ ने व्यवस्था दी कि संबंधित पक्ष तीन भवनों के बारे में आपसी सहमति के आधार पर किसी नतीते पर पहुंचें अथवा उन्हें बेंच कर आपस में पैसों का बंटवारा कर लें। इस मामले में तीन पीढ़ियों के अट्ठावन सदस्य पक्षकार बन चुके थे।

बचपन में बुजुर्गों से अक्सर सुनता था, कि भगवान, दुश्मन को भी कचहरी और अस्पताल का मुंह न दिखाए। असल में मुक़दमा हमेशा मुवक्किल यानि वादी प्रतिवादी ही लड़ता है, जीतता हारता है, वकील नहीं। वकील तो सिर्फ उसे निचोड़ता रहता है, तारीख-दर तारीख़। वह तारीख़ लेता रहता है और अक्सर उसमें भी ग़फलत पैदा करता है। वकील कभी नहीं चाहता कि मुकदमे का अंत हो। वह चाहता है कि मुक़दमा चलता रहे तब तक, जब तक उसकी या मुवक्किल की ज़िन्दगी चलती रहे। वादी प्रतिवादी यानि पक्षकार अगर नौकरीपेशा है, हर तारीख़ पर नहीं पहुंच सकता, मुक़दमा नहीं देख सकता, तो उसे भगवान भी मुकदमा नहीं जिता सकते, न्याय नहीं दिला सकते। यह सिर्फ वकीलों का नहीं, बल्कि पूरी कचहरी का व्यवहार है।

अगर पास में अकूत पैसा है तो आप कोई भी मुकदमा जीत सकते हैं, किसी भी हारते हुए मुक़दमे में पेंच पैदा कर सकते हैं। नोटिस तामील हुए बिना किसी की नामौजूदगी, प्राप्ति अथवा लेने से इंकार जैसी टिप्पणी स्वत: दर्ज होकर अदालत में वापस आ सकती है तथा उसके ख़िलाफ़ स्थगनादेश अथवा अन्य कोई आदेश बेहिचक जारी हो जा सकता है, पैसे के बलबूते। दलाल वकीलों का वर्चस्व है। ऐसे-ऐसे लोग वकालत के पेशे में है, जो मनसा-वाचा-कर्मणा दूर दूर तक वकील नहीं है। पेशकार, लिपिक, अर्दली जैसे कर्मी खुद को कलेक्टर से कम नहीं आंकते। फोटोकॉपी करने वाले, टाइपिस्ट आदि भी पक्षकार को यों देखते हैं, जैसे बहुत गरज़मंद हो।

कानुपर ग्रामीण निवासिनी एक महिला मारपीट जैसा छोटा मुक़दमा लड़ते-लड़ते अपनी दर्जनभर से ज़्यादा बकरियां बेच बैठी। एक दिन उसने कचहरी आना ही बंद कर दिया। मुवक्किल अगर अनपढ़ है, गरीब है तो वह वकील साहब के लिए हैंडपंप से पानी लाता है, बाजार से चाय लाता है खुद जाकर। ज़रूरत पड़ने पर कुर्सियां बेंच तक साफ करता है। आप अगर वकील को चाय नाश्ते या भोजन के लिए बाहर ले जाना चाहें, तो वह दो-चार साथी अपने साथ ज़रूर कर लेता है। फिर अपने हिसाब से खाता खिलाता है, पैसे तो मुवक्किल देगा ही। वकीलों द्वारा साथियों को साथ ले जाना भी एक गुप्त समझौता है।

2016 के सितम्बर माह में छत्तीसगढ़ स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा था कि अगर जज ईमानदार नहीं होगा, तो दुकानदार हो जएगा, रुपए लेकर न्याय बेचेगा। जज अपने काम को नौकरी न समझें, बल्कि इसे ईश्वर प्रदत्त सम्मान मान कर तपस्वी की तरह काम करें। उन्होंने कहा, जज के साथ-साथ उनके स्टाफ को भी ईमानदार होना चाहिए। न्यायमूर्ति ठाकुर की इस टिप्पणी के ठीक एक पखवाड़े के बाद यानि 28-29 सितम्बर की रात सीबीआई ने दिल्ली के तीस हज़ारी कोर्ट की वरिष्ठ सिविल जज रचना तिवारी लखनपाल को चार लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रचना के घर से 94 लाख रुपए की नक़दी बरामद हुई। उन्होंने एक विवादित संपत्ति के मुक़दमे में एकपक्षीय फैसला सुनाने के एवज में बीस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें एक लोकल कमीशनर और स्वयं जज के पति भी संलिप्त थे। तीनों के ख़िलाफ़ न सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 व 8 के तहत मुक़दमा दर्ज हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने जज रचना तिवारी को निलंबित भी कर दिया।

देश में मुक़दमों की बाढ़ और न्याय मिलने में विलंब को लेकर न्यायमूर्ति ठाकुर की टिप्पणी थी कि अमेरिका में प्रति दस लाख की आबादी पर एक सौ पचास जज है, जबकि भारत में सिर्फ 12 हैं।, प्रति दस लाख की आबादी पर पचास जज रखने का प्रस्ताव है, जो आज तक अंजाम तक नहीं पहुंचा। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में सत्तावन लाख मुक़दमें विचाराधीन हैं, जिसमें बयालीस लाख मुकदमें आपराधिक मामलों के हैं और पन्द्रह लाख सिविल के। जबकि जजों की संख्या महज़ साढ़े तीन हजार है यानि हर जज के ज़िम्मे डेढ़ हज़ार से ज़्यादा मुक़दमे हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण टंडन ने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (जेटीआरआइ), लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (यूपीएसएल एसए) की कांफ्रेंस में उक्त आंकड़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए यहां तक कह डाला कि ज़मीन, मकान दुकान से कब्ज़ा हटाने के लिए लोग कोर्ट केस करने के बजाय गुंडों को पैसा देने लगे हैं। इसलिए न्यायपालिका में विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, अन्यथा लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। देश के सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में 56 हज़ार से ज़्यादा मामले लंबित हैं, जिसमें तकरीबन 24 हज़ार सिविल के और 33 हज़ार आपराधिक मामले हैं। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में तकरीबन साढ़े अड़तीस लाख मुक़दमे अपने निस्तारण की राह देख रहे हैं।❑❑

**हमारी न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विभिन्न ख़ामियां ग़रीब, बेसहारा पीड़ित पक्ष को अंतिम समय तक हलकान किए रहती है। तारीख़ पर तारीख़, समन दर समन और ऐसी तमाम कार्यवाहियां प्रक्रियाएं साधनहीन- निर्धनवादी को हतोत्साहित करती जाती है और न्याय व्यवस्था के प्रति उसका भरोसा टूटता जाता है। हर पेशी पर मुंशी, वकील, पेशकार जैसी ड्योढियां जैसे-जैसे तय होती हैं, वैसे-वैसे जेब ख़ाली होती जाती है और शाम ढले जब वादी थका हारा घर लौटता है, तो उसके पास अगली तारीख़ लिखी पर्ची और निराशा के अलावा कुछ नहीं होता। मुक़दमा क़ायम कराने वाला अपने जीवन में उसका अंतिम फैसला देख ले, तो बड़े भाग्य की बात समझी जाती है। वरना उस मुक़दमे को पोते-पड़पोते ही निर्णीत करा पाते हैं अथवा वे भी लड़ते रहते हैं। जनवरी, 2017 में दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने पारिवारिक संपत्ति विवाद के एक मामले में अपना उल्लेखनीय फैसला सुनाया।**

# कैसे रुकेगी भोजन की बर्बादी

रमेश सर्राफ धमोरा

पिछले दिनों प्रधानमंत्री की मन की बात में देशवासियों को भोजन की बर्बादी के प्रति आगह किया। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए यह पाठ पढ़ना ज़रूरी है। यों भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का दर्जा प्राप्त है और यही कारण है कि भोजन जूठा छोड़ना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है। मगर आधुनिकता की अंध ी दौड़ में हम अपना यह संस्कार भूल गए हें। होटल रेस्तरां के साथ ही शादी ब्याह जैसे आयोजनों में सैकड़ों टन ख़ाना रोज़ बर्बाद हो रहा है। भारत ही नहीं, समूचि दुनिया का यही हाल है। एक तरफ करोड़ों लोग दाने दाने को मोहताज है कुपोषण का शिकार हैं, वही रोज़ लाखों टन खाना बर्बाद किया जा रहा है।

दुनियाभर में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका एक तिहाई यानि लगभग 1 अरब 30 लाख टन बर्बाद चला जाता है। बर्बाद जाने वाला भोजना इतना होता है कि उससे दो अरब लोगों की खाने की ज़रूरत पूरी हो सकती है। विश्वभर में होने वाली भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और विश्व विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एकजुट होकर एक परियोजना शुरू की है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में बढ़ती सम्पन्ता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही हैं आज भी देश में विवाह-स्थलों के पास रखे कूड़ाघरों में चालीस प्रतिशत से अधिक खाना फेंका हुआ मिलता है।

विश्व खाद्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का हर सातवां व्यक्ति भूखा सोता है। अगर इस बर्बादी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। विश्व भूख सूचकांक में भारत का 67वां स्थान है। देश में हर साल 25.1 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है लेकिन हर चौथा भारतीय भूखा सोता है। इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल और 21 करोड़ टन सब्जियां वितरण प्रणाली में ख़ामियों के कारण ख़राब हो जाती हैं।

विश्व खाद्य संगठन के मुताबिक भारत में हर साल पचास हज़ार करोड़ रुपए का भोजन बर्बाद चला जाता है, जो कि देश के खाद्य उत्पादर का चालीस प्रतिशत है। इस अपव्यय का दुष्प्रभाव हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। हमारा देश पानी की कमी से जूझ रहा है। लेकिन अपव्यय किए जाने वाले इस भोजन को पैदा करने में इतना पानी व्यर्थ चला जाता है जिससे दस करोड़ लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। एक आंकलन के मुताबिक अपव्यय के बराबर की ध नराशि से पांच करोड़ बच्चों की ज़िन्दगी संवारी जा सकती है। चालीस लाख लोगों को ग़रीबी के चंगुल से मुक्त किया जा सकता है और पांच करोड़ लोगों को आहार सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है।

**विश्व खाद्य संगठन के मुताबिक भारत में हर साल पचास हज़ार करोड़ रुपए का भोजन बर्बाद चला जाता है, जो कि देश के खाद्य उत्पादर का चालीस प्रतिशत है। इस अपव्यय का दुष्प्रभाव हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। हमारा देश पानी की कमी से जूझ रहा है। लेकिन अपव्यय किए जाने वाले इस भोजन को पैदा करने में इतना पानी व्यर्थ चला जाता है जिससे दस करोड़ लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। एक आंकलन के मुताबिक अपव्यय के बराबर की धनराशि से पांच करोड़ बच्चों की ज़िन्दगी संवारी जा सकती है। चालीस लाख लोगों को ग़रीबी के चंगुल से मुक्त किया जा सकता है और पांच करोड़ लोगों को आहार सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। भारत में हर साल पांच साल से कम उम्र के दस लाख बच्चों के भूख या कुपोषण से मरने के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र ने जारी किए हैं। देश के 51.14 प्रतिशत परिवारों की आय का ज़रिया महज़ अस्थायी मज़दूरी है। 4.08 लाख परिवार कूड़ा बीन कर तो 6.68 लाख परिवार भीख मांग कर अपना गुज़ारा करते हैं।**

भारत में हर साल पांच साल से कम उम्र के दस लाख बच्चों के भूख या कुपोषण से मरने के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र ने जारी किए हैं। देश के 51.14 प्रतिशत परिवारों की आय का ज़रिया महज़ अस्थायी मज़दूरी है। 4.08 लाख परिवार कूड़ा बीन कर तो 6.68 लाख परिवार भीख मांग कर अपना गुज़ारा करते हैं। गांव में रहने वाले 39.39 प्रतिशत परिवारों की औसत मासिक आय दस हज़ार रुपए से भी कम है।

ये तथ्य भी विचारणीय हैं कि हमारे देश में हर साल उतना गेहूं बर्बाद होता है जितना आस्ट्रेलिया की कुल पैदावार है। नष्ट हुए गेहूं की कीमत लगभग पचास हज़ार करोड़ होती है और इससे तीस करोड़ लोगों को साल भर भरपेट खाना दिया जा सकता है। हमारा 2. 1 करोड़ टन अनाज केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसे रखने के लिए हमारे पास माकूल भंडारण की सुविधा नहीं है। देश के कुल उत्पादित फल सब्जी का चालीय प्रतिशत समय पर मंडी तक नहीं पहुंच पाने के कारण सड़ गल जाता है।

औसतन हर भारतीय एक साल में छह से ग्यारह किलो अन्न बर्बाद करता हैं जितना अन्न हम एक साल में बर्बाद करते हैं उसकी कीमत से ही कई सौ कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकते हैं जो फल सब्जी को सड़ने से बचा सकें। एक साल में जितना सरकारी खरीदी का धान व गेहूं खुले में पड़े होने के कारण नष्ट हो जाता है, उससे ग्रामीण अंचलों में पांच हजार गोदाम बनाए जा सकते हैं। यदि पंचायत स्तर पर ही एक क्विंटल अनाज के आकस्मिक भंडारण व उसे ज़रूरतमंद को देने की नीति का पालन हो तो कोई भूखा नहीं मरेगा।

भोजन का फेंका जाना पहली निगाह में भले ही मामूली सी बात प्रतीत हो या फिर एक बड़े कार्यक्रम की अपरिहार्यता बता कर इससे पल्ला झाड़ लिया जाए, लेकिन यह एक गंभीर मसला है। इस संदर्भ में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। भोजन के अपव्यय से जल, ज़मीन और जलवायु के साथ-साथ जैव विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है।

रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादित भोजन, जिसे खाया नहीं जाता, उससे प्रत्येक वर्ष रूस की वोल्गा नदी के जल के बराबर जल की बर्बादी होती है। अपव्यय किए जाने वाले इस भोजन की वजह से तीन अरब टन से भी ज़्यादा मात्रा में खतरनाक ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। दुनिया की लगभग 28 प्रतिशत भूमि, जिसका क्षेत्रफल 1.4 अरब हेक्टेयर है, ऐसे खाद्यान्न को उत्पन्न करने में व्यर्थ होती है यह रिपोर्ट ख़तरे की घंटी है, जो बताती है कि हमारी लापरवाही और अनुचित गतिविधि यों के कारण, पैदा किए जाने वाले अनाज का एक तिहाई हिस्सा यानि करीब 1.3 अरब टन अनाज बर्बाद चला जाता है, वहीं 87 करोड़ लोग भूखे सोने के लिए विवश है।

हमारे यहां शादियों, उत्सवों या त्यौहारों में होने वाली भोजन की बर्बादी से हम सब वाक़िफ़ हैं। इन अवसरों पर ढेर सारा खाना कचरे में चला जाता है। कई बार तो घरों के आसपास फेंके गए भोजन से उठने वाली दुर्गंध व सड़ांध वहां रहने वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है, सड़ते भोजन से जानवरों की मौतों की ख़बरें हम पढ़ते रहते हैं। शादियों में खाने की बर्बादी को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। 2011 में खाद्य मंत्रालय ने कहा था कि वह शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार कर रहा है। इस बारे में विवाह समारोह (दिखावटी प्रदर्शन और फिजूलखर्च पर प्रतिबंध) अधिनियम 2006, भी बनाया गया है। अलबत्ता यह सख़्ती से लागू नहीं होता।

खाने की बर्बादी रोकने की दिशा में महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। खासकर बच्चों में शुरू से यह आदत डालनी होगी कि उतनी ही थाली में परोसें जितनी भूख हो। एक दूसरे से बांट कर खाना भी भोजन की बर्बादी को बड़ी हद तक रोक सकता है।

भोजन और खाद्यान्न की बर्बादी रोकने के लिए हमें अपने दर्शन और परंपराओं का स्मरण करने तथा अपनी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है। धर्म गुरुओं और स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। ❑❑

## ख़ास ख़बरें

### श्रीलंका: इस्तीफा नहीं देंगे राष्ट्रपति बहुमत वाले दल को सौंपेगे सत्ता

कोलंबो : श्रीलंका में जारी आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच विपक्ष ने राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांगा हैं जनता भी सड़कों पर गोतबाया के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रही है जबकि राष्ट्रपति द्वारा एकता सरकार बनाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद गोतबाया ने इस्तीफे की मांग ख़ारिज कर कहा, वह उसी स्थिति में सत्ता सौंपेगे जब कोई दल 225 वाली असेंबली में 113 सांसदों के साथ बहुमत साबित कर देगा।

### बूका में हुई हत्याओं की स्वतंत्र जांच हो : भारत

संयुक्त राष्ट्र : भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद को यूक्रेन पर हुई सभा में बूका में हुई हत्याओं की निंदा की और इसकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग का समर्थन किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, यूक्रेन ने बूका शहर में लोगों की हत्याएं बुरी तरह परेशान करने वाली हैं। इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। तिरुमूर्ति ने कहा, जब भी निर्दोष इंसानों की ज़िन्दगी दांव पर हो, तब कूटनीति ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प बचता है।

### कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट फिर भी बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम

नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, फिर भी भारत में तेल कंपनियों ने 15 दिन में 13वीं बार मूल्य वृद्धि करते हुए पेट्रोल और डीजल पर 80 पैसा बढ़ा दिया। इसे मिलाकर 15 दिन पहले के मुक़ाबले इनकी कीमत 9.20 रुपये बढ़ चुकी है। जबकि भारत को मिलने वाले कच्चे तेल में 24 मार्च से एक अप्रैल के बीच ही 14 डॉलर तक की गिरावट दर्ज की गई थी।

### तीनों निगमों के एकीकरण बिल को संसद की मंज़ूरी

दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक करने वाले दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल-2022 को राज्यसभा ने भी अपनी मंज़ूरी दे दी। विपक्ष के सभी संशोधनों की मांग को ख़ारिज करते हुए सदन ने इस बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने पहले ही इस बिल को पास कर दिया था। बिल के मुताबिक, तीनों निगमों के एकीकरण में संसाध नों का बेहतर इस्तेमाल होगा व रणनीतिक योजना बनाने में मदद मिलेगी। बिल पर चर्चा करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने निगमों के साथ सौतेला व्यवहार के कारण यह ज़रूरी हो गया था।

# रोज़े की कज़ा और कफ़्फ़ारा

**रोज़े की कज़ा व कफ्फारा**

दूसरी वह जिनसे कज़ा व कफ्फारा दोनों वाजिब होते हैं वह मुफसदात जिन से सिर्फ कज़ा वाजिब होती है वह 13 हैं:- किसी ने जबरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वह हलक़ से नीचे उतर गई। 2. रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक्त बिला क़सद हलक़ में पानी उतर गया। 3. क़ै (उल्टी) आयी और क़सदन (जान बूझकर) हलक़ में लौटा ली। 4. कसदन मुंह भर के क़ै (उलटी) कर ली। 5. कंकरी पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी या कागज़ का टुकड़ा कसदन निगल लिया। 6. दांतों में रही हुई चीज़ जबकि चने के दाने के बराबर हो खा लेना। 7. कान में तेल डालना। 8. नास लेना। 9. दांतों से निकले हुए खूंन को निगल लेना जबकि खून थूक पर ग़ालिब आ जाए। 10. भूले से कुछ खा-पी लिया फिर यह समझ कर कि रोज़ा टूट गया कसदन खा पी लेना। 11. यह समझ कर कि अभी सुबह सादिक़ नहीं हुई सेहरी खा ली फिर मालूम हुआ कि सुबह सादिक़ हो चुकी थी। 12. रमज़ान शरीफ के सिवा और दिनों में कोई और रोज़ा कसदन तोड़ लेना। 13. अब्र या गुबार की वजह से यह समझ कर कि आफताब गुरूब हो गया, रोज़ा इफ्तार कर लिया हालांकि अभी दिन था।

**वह चीज़ें जिन से कज़ा और कफ्फ़ारा दोनों वाजिब होते हैं**

ये तीन हैं:- 1. ऐसी चीज़ जो गिज़ा या दवा या लज़्ज़त के तौर पर इस्तेमाल होती हैं कसदन खा- पी लेना। 2. कसदन (जान बूझकर) सोहबत करना। 3. कसदन गन्दा खून निकलवाना। 4. सुरमा लगा लेना फिर यह समझ कर कि रोज़ा टूट गया कसदन, खा-पी लेना।

(आलमगीरी, नूरूलएज़ाह)

**रोज़े का कफ्फ़ारा**

कफ्फ़ारा तीन तरह से अदा होता है:-

1. एक गुलाम आजाद करे लेकिन अब मुद्दत से गुलामियत का दौर खत्म हो चुका है। इस लिए सिर्फ दो सूरतों में कफ्फारा दिया जा सकता है। 2. दो महीना लगातार रोज़े रखे। 3. अगर इसकी ताक़त न हो तो 60 मिस्कीनों को पेटभर के दोनों वक्त का खाना खिलाएं। या 60 मिस्कीनों को प्रति आदमी सदक़ा फितर की मिक्दार यानि एक किलो छह सौ छत्तीस ग्राम गेहूं या इस की कीमत अदा करे। (नूरूलएज़ाह-143)

रमज़ान में रोज़ा न रखने का उज़्र

1. बीमारी की वजह से ताक़त न होना या मर्ज़ बढ़ने का शदीद खतरा हो।

2. वह हामला या दूध पिलाने वाली औरत जिसको अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो।

3. मुसाफिर शरअी (जो सवा सत्तर किलो मीटर या उस से ज़्यादा कहीं जाने का इरादा करके अपनी बस्तियों की इमारतों से बाहर निकल आए)।

4. किसी को क़त्ल की धमकी देकर रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया जाएं तो उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है।

5. किसी बीमारी या भूख प्यास का इतना ग़लबा हो कि जान का ख़तरा लाहक हो तो रोज़ा तोड़ना जायज़ है।

6. हैज़ और निफास (मासिक धर्म) वाली औरत।

**निर्देश:**- इन सारी स्थितियों में रमज़ान के बाद कज़ा लाज़िम है।

रोज़े से सम्बन्धी ग़लत बातें

**मसला:**- कुछ लोग समझते हैं कि नफ़्ल रोज़े की सेहरी नहीं होती यह ग़लत है सेहरी करना सुन्नत है। रोज़ा फर्ज़ हो या नफ़्ली सब बराबर है।

**मसला:**- कुछ मंझले रोज़ा को अफज़ल समझते हैं और एक एतकाद यह है कि किसी की इफ्तारी से रोज़ा न खोलो वरना सारा सवाब उसी को मिल जाएगा यह बेअसल बात है।

**मसला:**- अक्सर लोग यह समझते हैं कि ईद की रात में रोज़ा होता है और सुबह को कहते हैं कि रोज़ा खोल लो यह बिल्कुल बेअसल बात है।

**मसला:**- कुछ जगह रिवाज़ है कि जब बच्चे को रोज़ा रखवाते हैं तो इफ्तार के वक़्त इसके गले में हार डालते हैं और एक दो देग़ खाना पका कर दोस्त व अहबाब को खिलाते हैं और इफ्तार के लिए मस्जिद में भेजते हैं सो शरीअत में इसका कोई सबूत नहीं बल्कि यह रस्म बिदअत और गुनाह है।

**मसला:**- कुछ जगह नफ्ली रोज़ों की सहरी में जगाने के लिए रमज़ान जैसा प्रबंध किया जाता है, जैसे- घंटी बजाना, ऐलान कराना इत्यादि यह सिर्फ लोगों के मनगढ़ंत और शरयन नापसंदीदा हैं।

**मसला:**- मशहूर है कि अकेला रोज़ा बगैर जोड़े के यूं ही इधर उधर भटकता रहता है यह भी सिर्फ मनगढ़ंत बात है। (अग़लातुल अवाम)

**चेतावनी:**- शव्वाल के महीने में 6 दिन नफ़्ल रोज़ा रखने की फज़ीलत और दूसरे नफ्ल रोज़ों से बहुत ज़्यादा है जिनको कि शश ईद के रोज़े कहते हैं लेकिन इसमें कुछ लोग यह समझते हैं कि अगर इनको ईद के अगले ही दिन से शुरू कर दें तब तो वह सवाब मिलता है वरना नहीं मिलता। तो यह ख़्याल गलत है बल्कि अगर महीने भर में उन को पूरा कर लिया तो सवाब मिलेगा चाहे ईद के अगले ही दिन शुरू करें या बाद को शुरू करें और चाहे लगातार रखें या विभिन्न तरह से हर तरह से सवाब मिलेगा।

कुछ लोग इन छह रोज़ों में अपने पिछले कज़ा के रोज़ों को जोड़ लेते हैं कि शश ईद के रोज़े भी हो गए और कज़ा भी अदा हो गयी, तो ख़ूब समझ लो कि इनमें कज़ा की नीयत करने से वह फज़ीलत शश ईद की हासिल न होगी। कज़ा अलग अदा करें और इन को सवाब के लिए अलग रखें। गो कुछ किताबों में इसको लिख दिया है लेकिन क़ायदे के ख़िलाफ़ होने से वह सही नहीं यह अच्छी तरह समझ लो। ❑❑

## नअ्त शरीफ़

दिलों के गुलशन महक रहे हैं ये क़ैफ़ क्यों आज आ रहे हैं
कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुज़ूर तशरीफ़ ला रहे हैं
कहां का मंसब कहां की दौलत क़सम ख़ुदा की ये है हक़ीक़त
जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीना को जो रहे हैं
हबीबे दावर ग़रीब परवर रसूले अकरम करम के पैकर
किसी को दर पर बुला रहे हैं किसी के ख़्वाबों में आ रहे हैं
न पास पी हो तो सूना सावन वो जिस पर राज़ी वही सुहागन
जिन्होंने थामा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं
नवाज़िशों पे नवाज़िशें हैं इनायतों पे इनायते हैं
नबी की नअ्तें सुना सुनाकर हम अपनी क़िस्मत जगा रहे हैं
बनेगा जाने का फिर बहाना कहेगा आकर कोई दीवाना
चलो नियाज़ी तुम्हीं मदीने, मदीने आक़ा बुला रहे हैं।

## नूरे क़ुरआन

### ( सूरा अल बकरह नं॰ 02 )

### अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

**और उनके लिए वहां साफ पाक की हुई बीवियां हैं, और वे लोग सदैव वहीं रहेंगे।**

जन्नत की औरतें हर प्रकार की मलिनता से पाक (पवित्र) साफ होंगी, चाहे शारीरिक मलिनता हो या चरित्रिक।

यहां तक तीन ऐसी वस्तुएं जिनका जानना आवश्यक था बयान की गई। प्रथम हम वहां से आये और क्या थे, 2. दूसरा कि क्या खाये और कहां रहें 3, तीसरा यह कि हमारा परिणाम क्या होगा?

**नि:संदेह अल्लाह इस बात से लज्जित नहीं होता कि कोई उदाहरण बयान करे मच्छर का या उस वस्तु का जो उससे बढ़कर है।**

इस आयात में उस आपत्ति का उत्तर दिया गया जो इनकारियों की ओर से पहली आयत पर हुई। उसका सारांश यह है कि जब छोटी सी सूरा भी इस कलाम जैसी उनसे न हो सकी और इसी से उसका अल्लाह का कलाम होना सिद्ध हो चुका हो इनकारियों ने कहा कि यद्यपि हम उस कलाम के समक्ष तो विवश हैं, परंतु हम दूसरी युक्ति से यह बात सिद्ध करते हैं कि कुरआन अल्लाह का कलाम नहीं, बल्कि मनुष्य की रचना है और वह युक्ति यह है कि महान अपने कलाम में तुच्छ और छोटी वस्तुओं के वर्णन से बचा करते हैं। अल्लाह जो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ हैं, जिसने कैसे अपने कलाम में मक्खी और मकड़ी का वर्णन कर दिया? इस आपत्ति का उत्तर दिया गया कि इसमें कोई लज्जा की बात नहीं कि अल्लाह मच्छर या उससे बड़ी वस्तु जैसे मक्खी और मकड़ी, का उदाहरण प्रस्तुत करें क्योंकि उदाहरण तो किसी वर्णनीय वस्तु का भाव प्रकट करने के लिए होता है। उसके तुच्छ होने से क्या प्रयोजन? भाव स्पष्टता का उद्देश्य तभी सिद्ध हो सकता है जब वर्णनीय वस्तु और उसके लिए दिए गये उदाहरण दोनों में समानता हो। जो वर्णनीय वस्तु है यदि वह तुच्छ और छोटी होगी तो उसके लिए दिया गया उदाहरण भी तुच्छ और छोटा होगा अन्यथा उदाहरण की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी, हां यदि उदाहरण, उदाहरण देने वाले में समानता और बराबरी आवश्यक होती तो उन मूर्खों की यह आलोचना ठीक हो सकती थी। और तौरेत और इंजील और विद्वानों और बादशाहों के कलाम में ऐसे उदाहरण बहुत अधिकता से पाये जाते हैं। इसके विपरीत कहना इनकारियों की शत्रुता और मूर्खता की बात है और जो 'उससे बढ़कर है' का अर्थ यह भी हो सकता है कि मच्छर से तुच्छ और छोटी होने में बढ़ी हुई हो। जैसे मच्छर का पर। जैसा कि कुछ हदीसों में दुनिया की तुच्छता दिखाने के लिए मच्छर के पर का उदाहरण दिया गया है।

**सो जो ईमान वाले हैं वे विश्वासपूर्वक जानते हैं कि यह उदाहरण ठीक है जो उनके पालनहार की ओर से उतरा है और जो इनकारी हैं सो वे कहते हैं अल्लाह का इस उदाहरण से क्या मतलब था, अल्लाह इस उदाहरण से बहुतों को भटकाता है और बहुतों को मार्ग दिखाता है।**

अर्थात् ईमान वाले तो इन उदाहरणों को लाभदायक और सच समझते हैं और इनकारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि ऐसी मामूली और तुच्छ मिसालों से अल्लाह का उद्देश्य क्या है? जवाब दिया गया कि इस कलाम से बहुतों को सीधा मार्ग दिखाना है और कुछ को पथ भ्रष्टता में फंसाये रखना है (अर्थात् सीधे चलने वाले को और टेढ़े चलने वालों को एक दूसरे से अलग-अलग दिखलाना है।)।

**और इस उदाहरण से अल्लाह केवल बुरे कार्य करने वालों को भटकता है जो कि अल्लाह से प्रतिज्ञा को पक्का करने के पश्चात् तोड़ते रहते हैं और जिस वस्तु को अल्लाह ने मिलाने को कहा है वे उसको काटते रहते हैं।**

जैसे रिश्तेदारी तोड़ देना रसूलों, प्रचारकों, विद्वानों, मोमिनों और नमाज़ों और दूसरी तमाम अच्छी बातों से मुंह मोड़ना।

**और मुल्क में कलह करते रहते हैं।**

कलह से तात्पर्य यह है कि लोगों को ईमान से नफ़रत दिलाते थे और इस्लाम के विरोधी लोगों को बहका चढ़ाकर मुसलमानों से लड़ाई कराते थे और सहाबा और उम्मत के लोगों में झूठी बुराईयां दिखाकर दुष्प्रचार करते थे ताकि रसूल और इस्लाम का सम्मान लोगों के दिलों में कम हो जाये और मुसलमानों की गुप्त बातें विरोधियों तक पहुंचाते थे और इस्लामी तरीक़े के विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रथायें फैलाने का प्रयत्न करते थे।

# पंजाब : क्या आम आदमी पार्टी राजनीतिक शून्य भर सकेगी

**विपिन पब्बी**

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की शानदार विजय तथा कांग्रेस को एक तरह से खत्म करने और भाजपा को धूल चटाने के और अन्य स्थानीय पार्टियों को उनकी हालत दिखाने के बाद 'आप' के लिए अपने पांव फैलाने के लिए अवसर बढ़ गए, राजनीतिक शून्य को भरने के लिए दरवाज़े खुल गए। पदासीन मुख्यमंत्रियों की संख्या को लेकर वर्तमान में यह कांग्रेस के बराबर है। 'आप' के नाम यह उपलब्धि भी है कि वह भाजपा तथा कांग्रेस के अतिरिक्त दो राज्यों में शासन करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी है। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अथवा राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियां भी अन्य राज्यों में प्रयास करने के बावजूद एक राज्य में ही सीमित हुई है।

इस वर्ष के अंत में गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में भाजपा का शासन है तथा अभी तक इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस रही है हालांकि कांग्रेस के ख़िलाफ़ वर्तमान भावनाओं को देखते हुए राजनीतिक स्थिति वैसी ही बनी रहने की संभावना नहीं है।

गुजरात में भाजपा 27 सालों से सत्ता में है। इसने लगातार पहले 05 विधानसभा चुनाव जीते हैं तथा संसदीय व स्थानीय निकाय चुनावों में भी अच्छी कारगुज़ारी दिखाई है। दूसरी ओर कांग्रेस बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है और स्थानीय नेतृत्व तथा काडर विकसित करने में असफल रही है। इसने गत विधान सभा चुनावों में भाजपा को टक्कर दी थी लेकिन उस समय 'आप' एक ऐसी शक्ति नहीं बनी थी जिसकी पहचान हो। 'आप' ने अब राज्य में सत्ता हथियाने की ठोस कोशिश करने का निर्णय किया है और राज्य में पहले ही अपने समर्थन आधार को सक्रिय कर दिया है। कहने की ज़रूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह दोनों अपने गृह राज्य में सत्ता में बने रहने के लिए अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास करेंगे। 'आप' की सत्ता विरोध ी वोट अपनी झोली में पड़ने की आशा है जबकि यह वोट प्राप्त करने के लिए अपने 'दिल्ली मॉडल' तथा 'पंजाब मॉडल' का ढोल पीटेगी।

हिमाचल प्रदेश एक अन्य राज्य है जहां 'आप' के लिए अच्छे अवसर हैं सत्ताधारी भाजपा हाल ही में राज्य में आयोजित सभी उप-चुनाव हार चुकी है जिनमें लोकसभा के लिए एक उपचुनाव भी शामिल है। यह राज्य में पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था और इसे जयराम ठाकुर नीत भाजपा सरकार के ख़िलाफ एक जनादेश के तौर पर देखा गया। यहां तक कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में भी चर्चा सुनाई दे रही हैं।

**'आप' ने हिमाचल प्रदेश में 06 अप्रैल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के के समकक्ष भगवंत मान द्वारा एक रैली को संबोधित कर अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया। रैली स्थान का चुनाव जो मंडी में जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र है, एक स्पष्ट संकेत है कि 'आप' का उद्देश्य कुछ कर दिखाना है तथा यह एक आक्रामक चुनाव प्रचार की शुरूआत है।**

राज्य में चार दशकों से अधिक समय तक डटे रहे अपने सबसे बड़े क़द के नेता वीरभद्र सिंह के निधन के बाद राज्य में कांग्रेस उधेड़ बून में है। पार्टी एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करने अथवा एक ऐसा नेता पेश करने में सक्षम नहीं है जो विभिन्न धड़ों के लिए स्वीकार्य हो। यह हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा शून्य छोड़ देता है। एक छोटा राज्य होने के नाते 'आप' यहां एक प्रभावशाली चुनाव प्रचार चलाने में सक्षम होगी। राज्य में मतदाता भी पार्टी द्वारा दिल्ली में किए गए अच्छे कार्य के प्रति जागरुक हैं और बहुत ध्यानपूर्वक पंजाब में पार्टी की सरकार की कारगुज़ारी पर नज़र रखेंगे।

'आप' ने हिमाचल प्रदेश में 06 अप्रैल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के के समकक्ष भगवंत मान द्वारा एक रैली को संबोधित कर अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया। रैली स्थान का चुनाव जो मंडी में जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र है, एक स्पष्ट संकेत है कि 'आप' का उद्देश्य कुछ कर दिखाना है तथा यह एक आक्रामक चुनाव प्रचार की शुरूआत है। हालांकि पार्टी को राज्य के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की पहचान करनी है तथा शीर्ष पद के लिए इसके चेहरे का चयन करके अच्छा करेगी। संभवत: इसके बाद इसका उद्देश्य हरियाणा में अपना भाग्य आज़माना होगा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि राज्य में नेतृत्व के लिए यह संभवत: हरियाणा के विवादास्पद तथा बड़बोले आई.स.एस. अधिकारी खेमका को चुनेगी जिनके नाम अपने कैरियर में 54 बार स्थानांतरित किए जाने की विशेष उपलब्धि है। खेमका एक निष्ठावान व्यक्ति हैं और यह एक ऐसा गुण है जो लोग अब अपने नेताओं में देखना चाहते हैं।

स्वाभाविक है कि लोग तथा इसके राजनीतिक विरोधी पंजाब में 'आप' की कारगुज़ारी पर बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे जिसके बाद ही यह देश के अन्य हिस्सों में अपने पांव फैलाने में सक्षम होगी। ❑❑

# नगर निगम चुनाव - दिल्ली की नई जंग

05 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से दो दिन पहले केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ एक प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली की कालोनियों को नियमित करने के प्रावधानों में छूट देने की बात कही। इसे दिल्ली नगर निगम चुनावों से जोड़कर देखा गया। अगले दिन यानि 09 मार्च को दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग ने निगम चुनाव की तारीखें घोषित करने के लिए एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाई, लेकिन उप- राज्यपाल के संदेश का हवाला देखकर चुनाव टाल दिया गया।

संदेश यह था कि केन्द्र सरकार दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक करने का विधेयक संसद के इसी सत्र में लाने वाली है, लेकिन दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे आयोग के कामकाज में केन्द्र सरकार की दख़लंदाज़ी माना और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अर्ज़ी में कहा गया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की ख़तरे में है और नगर निगम चुनाव की तारीखें टालने का आयोग का फैसला मनमाना है।

सुप्रीम कोर्ट में तो इस अर्ज़ी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन केन्द्र सरकार तीनों नगर निगम को एक करने कार्य में आगे बढ़ गई है। नए विधेयक में नगर निगम के एकीकरण के साथ अगर सीटें (अभी तीनों नगर निगमों में कुल 272 सीटें हैं) घटाने-बढ़ाने का भी प्रावधान हुआ तो परिसीमन नए सिरे से होगा, जिसमें समय लगेगा।

आप नेता, मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि भाजपा की हार के डर से निगम चुनाव टाले गए हैं, आप के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक कहते हैं, ''2017 के चुनाव तक लोगों को पता नहीं था कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार क्या काम करती है और भाजपा के नेतृत्व वाला नगर निगम क्या काम करता है। लेकिन अब मोहल्लों में गंदगी से लोगों में गुस्सा है और हार के डर से भाजपा चुनाव डाल रही है। अगर एकीकरण ही मकसद था तो यह काम छह माह पहले भी हो सकता था, ''हालांकि, आप एकीकरण की विरोधी नहीं, बेहतर गर्वेंस की पक्षधर है।

प्रदेश भाजपा केजरीवाल सरकार पर नगर निगमों को पैसा देने में कोताही बरतने का आरोप लगाती है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर कहते हैं कि केजरीवाल सरकार तीसरे डीएफसी (दिल्ली वित्त आयोग) की सिफारिशों के आधार पर पैसा दे रही थी जबकि उसे पांचवें डीएफसी के हिसाब से देना था। निगम को पैसा देने में और भी कई तरह की कटौतियां की गई है।

दुर्गेश का कहना है कि अगर केजरीवाल सरकार ने फण्ड देने में नियमों का उल्लंघन किया है तो भाजपा अदालत का सहारा ले सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, नगर निगम में कर्मचारियों की तंख्वाह छह माह तक देर से मिल रही है, भाजपा नेता कह रहे हैं कि नए विधेयक में वित्त की वैधानिक ज़िम्मेदारी भी तय होने की उम्मीद है।

दिल्ली की तीसरी राजनैतिक शक्ति कांग्रेस को एकीकरण गंवारा नहीं है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी कहते हैं, '' एकीकरण से क्या मिलेगा, तीनों निगमों की वित्तीय हालत ख़राब है, उन्हें वित्तीय सहायता देनी चाहिए, 2012 में निगमों को इसलिए अलग किया गया था जबकि कमीश्नर, नेता और अफसर जनता के बीच पहुंचे। तीन कमिश्नर और तीन मेयर की जगह एक ही होगा तो लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी।

कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को 'आप' और 'भाजपा' की मिलीभगत मानती है। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी कहते हैं, 'निकाय चुनाव कराना पूरी तरह राज्य सरकार के

बाक़ी पेज 11 पर

## कोविड-19 ने संघ की शाखा वृद्धि पर लगाया अल्पविराम

कोरोना विषाणु संक्रमण महामारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखाओं पर भी अपना असर डाला है। महामारी के कारण शाखाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी पर अल्पविराम लग गया है। संघ ने माना है कि कोरोना महामारी के चलते उसकी शाखाओं की वृद्धि कम हुई है लेकिन इस कमी को अगले दो तीन माह में पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले शाखाओं की संख्या 5,000 से अधिक बढ़ी है लेकिन 2019 से 2022 के मार्च माह तक शाखाओं की वृद्धि 1663 ही रही।

इस वर्ष जारी वार्षिक प्रतिवेदन के मुताबिक देश में मार्च 2022 में 60,929 शाखाएं काम कर रही हैं। मार्च, 2021 में यह संख्या 55,692 थी। यानि एक साल के अंतराल में देश में शाखाओं की संख्या में 5277 की वृद्धि हुई। कोरोना महामारी के कारण 2020 में वार्षिक प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया था जबकि 2019 में देश में शाखाओं की संख्या 59,266 थी। मगर आंकड़ों पर ग़ौर करें तो हम पाते हैं कि 2019 से 2022 के बीच शाखाओं की संख्या में 1663 की बढ़ोत्तरी हुई जो बहुत मामूली है। यह काल कोरोना महामारी का काल रहा है।

वार्षिक प्रतिवेदन के मुताबिक 2012 से 2022 के बीच देश में 20,000 से अधिक शाखाओं की संख्या बढ़ी है। केन्द्र में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के आने के बाद से शाखाओं की संख्या में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हो रही है।

- वर्ष: 2012, शाखा: 40891
- वर्ष: 2014, शाखा: 44982
- वर्ष: 2015, शाखा: 51330
- वर्ष: 2016, शाखा: 56569
- वर्ष: 2017, शाखा: 57165
- वर्ष: 2018, शाखा: 58964
- वर्ष: 2019, शाखा: 59266
- वर्ष: 2021, शाखा: 55652
- वर्ष: 2022 (मार्च) शाखा: 60929

# क्रिकेट खेलतीं आदिवासी लड़कियाँ

मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले की जमीन उपजाऊ मानी जाती है और यहां की 70 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदाय से है लेकिन आर्थिक व सामाजिक रूप से अब भी यह इलाक़ा पिछड़ा हुआ हैं पिछड़ेपन के बावजूद यहां की आदिवासी लड़कियां क्रिकेट में अपना कमाल दिखा रही हैं। ज़िला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर वनग्राम चंद्रखाल की आदिवासी लड़कियों का विगत दिनों आपस में मैच हुआ जिसे देखने और शाबाशी देने के लिए बड़ी संख्या में शहर के लोग उमड़े। उत्सव जैसे इस माहौल में आसपास के 15 से अधिक गांवों की लड़कियां बैट और बॉल और बॉल से मैदान में एक-दूसरे को पछाड़ने में लगी थीं। सालों से भेदभाव की शिकार इन लड़कियों के लिए खुले मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना बहुत बड़ी उपलब्धि रही।

हालांकि यूनिफार्म में इन लड़कियों का क्रिकेट खेलन पहले किसी को मंज़ूर नहीं था, लेकिन इस धारणा को इन लड़कियों ने बदल डाला। पहले इन लड़कियों ने परिवार का भरोसा जीता, फिर समाज का। और उनके इस प्रयास को संभव बनाने में सहयोग किया सिनर्जी संस्थान ने। लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए इस संस्थान में चेंजलूमर कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लड़कियों की रुचि जानकार उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

गांव में आदिवासी लड़कियों के साथ कुछ मुस्लिम लड़कियों ने भी क्रिकेट खेलने में अपनी रुचि दिखाई, लेकिन शुरू में मात्र दो लड़कियों को परिवार वालों ने खेलने की अनुमति दी। मुस्लिम परिवार से तोशिबा कुरैशी और आदिवासी परिवार की हेमा मंडराई के प्रशिक्षण के लिए संस्थान ने अपनी ओर कोच की तालाश शुरू की। इसके लिए हरदा क्रिकेट एसोसिएशन से बात की गई, लेकिन लड़कियों की कोचिंग के लिए कोई कोच तैयार नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश के बाद संस्था को इस शर्त पर कामयाबी मिली कि संस्था का कोई पदाधिकारी लड़कियों की प्रेक्टिस के दौरान मैदान पर मौजूद रहेगा। दो लड़कियों से शुरू हुई इस मुहिम में एक साल के भीतर 15 लड़कियां शामिल हो गईं, जो लड़कियों में उम्मीद जगाने के लिए बड़ी बात थी।

इन लड़कियों ने अपनी मेहनत और गुल्लक के जमा पैसे बैट बॉल खरीदे। हालांकि इसमें कुछ संस्थानों ने भी योगदान दिया। इस तरह शुरू हुई लड़कियों की क्रिकेट टीम। आज जब इनका टूर्नामेंट होता है तो संस्था के अलावा पंचायत और वन विभाग, इनके टूर्नामेंट के लिए मैदान को समतल बनाता है, दर्शकों के बैठने के लिए टेंट लगाता है, नेहरू युव केन्द्र विजेताओं के लिए स्मृति चिह्न तैयार करवाता है। संस्था की ओर से पुरस्कार में नगद राशि दी जाती है। अब स्थिति यह है कि 15 गांवों की लड़कियों के बीच टूर्नामेंट होने लगा है।

कभी उनका विरोध करने वाले लोग अब उन्हें मैदान में शाबादी देने से नहीं चूकते। गांव के लोगों की सोच भी बदलने लगी हैं विमल जाट बताते हैं कि चार साल पहले स्थानीय लड़कियों की रुचि को देखते हुए यहां महिला क्रिकेट टीम की शुरुआत की गई थी। आज यह टीम राज्य और संभाग स्तर पर खेल रही हैं अब मैदान में लड़कियां अपने आपको असहज महसूस नहीं करतीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। इन्हें देखकर गांव की अन्य लड़कियां भी प्रेरित हो रही हैं।

टूर्नामेंट खेल रही सिगोन गांव की शीला शादीशुदा है, वह बताती है कि

बाक़ी पेज 11 पर

## 10 करोड़ के टैग का कोई दबाव नहीं : प्रसिद्ध कृष्णा

**सवाल:**- टी-20 क्रिकेट में आपकी सभी 24 गेंद अलग अलग तरह की होती हैं और आप खेल के विभिन्न चरणों में गेंदबाज़ी करते हैं आप अपने खेल की योजना कैसे तैयार करते हैं?

**जवाब:**- हाँ, ये 24 अलग गेंद होती हैं, लेकिन आप वैसे ही दौड़ते हुए आते हैं और वही काम करते हैं, उसी तरह की अच्छी गेंद डालने की कोशिश करते हैं। लाल गेंद हो, 50 ओवर का प्रारूप हो या टी-20 अच्छी गेंद आमतौर पर वैसे ही लेंथ होती है, जो बाहर की ओर जाती हैं। एक अच्छी यार्कर सभी प्रारूपों में एक अच्छी यार्कर होती है।

**सवाल:**- आप इस सत्र में लसित मलिंगा के साथ काम करेंगे। आपकी गेंदबाज़ी के किसी खास पहलू पर आप काम करना चाहेंगे.?

**जवाब:**- जैसे ही मैंने टवीटर पर उस पोस्ट को देखा जिसमें कहा गया था कि मलिंगा को राजस्थान रायल्स के गेंदबाज़ी कोच के तौर पर लाया जा रहा है तो मुझे लगा कि यह बहुत ही रोमांचक है क्योंकि हम सभी ने देखा है कि मलिंगा ने विश्व क्रिकेट के लिए सालों से क्या किया है और उन्होंने टी-20 क्रिकेट में क्या किया हैं उन्होंने जिस तरह के एक्शन के साथ गेंदबाज़ी की वह विश्वसनीय था। मैंने कई तरह के कोचों से बातें की हैं, लेकिन मलिंगा एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन किया। उनका टीम से जुड़ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित करने वाला था। वह चीज़ों को बहुत सरल रखने की कोशिश करते हैं। मेरी भी यही सोच है।

**सवाल:**- क्या नीलामी की आपकी कीमत (10 करोड़) आप पर अतिरिक्त प्रदर्शन का दबाव डालती है?

**जवाब:**- बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने एक साथ भारतीय टीम में चर्चा की थी कि भुगतान की जाने वाली राशि पर ध्यान नहीं देना है। मूल रूप से अधिक पैसा आपको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं बनाता है। यह नीलामी और कई अन्य चीज़ें हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी तरह का अंतर आता है।

**सवाल:**- राजस्थान रायल्स की टीम में कर्नाटक के कुछ खिलाड़ी हैं। क्या यह आपको कम्फर्ट जोन में रखता है?

**जवाब:**- राजस्थान रायल्स मेरे लिए एक नया सेटअप था और ज़ाहिर है जब आप राजस्थान रायल्स जैसे नए सेटअप में आते हैं और वहां कर्नाटक के ही लड़के होते हैं तो स्पष्ट रूप से वे चीजों को जानने में मेरी मदद करते हैं। जब आप एक ऐसी लीग में आते हो जहां दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी आते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ❑❑



# औषधीय पौधों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार

हमारे शरीर को निरोगी बनाये रखने में औषधीय पौधों का अत्याधिक महत्व होता है। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी-बूटियां चिकित्सकों द्वारा मानव रोगोपचार हेतू अमल में लाई जाती हैं।

यहीं नहीं, जंगलों में खुद-ब-खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अदभुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिद्ध विद्वान् चरक ने तो हरेक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतू कई अनमोल किताबों की रचना कर डाली है जिसका प्रयोग आजकल मानव का कल्याण करने के लिए किया जा रहा है। आयुर्वेद के अनुसार, औषधीय पौधों के संपर्क में आने मात्र से ही व्यक्ति के अनेक प्रकार के कीटाणुओं का स्वत: नाश हो जाता है जबकि इससे निकलने वाली वायु से शरीर को काफी लाभ पहुंचता है और संपूर्ण वातावरण प्रदूषण रहित हो जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह समूचा पौधा ही हमारे उत्तम स्वास्थ्य हेतू अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसकी पत्तियां, तना, फूल और जड़ सभी तरह से मानव रूपी जीवन में रोगों से निजात पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति औषधीय पौधों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करके स्वस्थ हो जाता है परन्तु यहां ध्यान देने योग्य बात यही है कि इन सभी बहुमूल्य औषधीय पौधों से रोगों की चिकित्सा करना मुश्किल नहीं है अपितु उसकी पहचान करते हुए उपयोग की विधि को भली भांति जानना अति अनिवार्य है।

### चमेली

यूँ तो फूलों की रानी कहलाने वाली चमेली की पत्ती एवं फूलों से सभी वाक़िफ़ हैं किन्तु मुंह के छाले और मासिक धर्म की रुकावट को दूर करने में यह बहुत ही सक्षम है। इसके लिए भी जन सामान्य में पहचान एवं उपयोग संबंधी जानकारी अति आवश्यक है।

### तुलसी

संसार के विभिन्न औषधीय पौधों में तुलसी नामक पौधे में रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने की विशिष्ट शक्ति पायी जाती है क्योंकि तुलसी के पत्तों में पीलापन लिए हुए हरे रंग का तेल विद्यमान होता है, जो उड़नशील होता है। यह तेल पत्तियों से निकलकर धीरे-धीरे हवा में फैलने लगता है। फलस्वरूप, तुलसी के निकट आने वाली वायु जहां भी जाती है उसके संपर्क मेंआने वाले समस्त लोगों के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम कही जाती है। तुलसी की पत्ती, तना और बीज व्यक्ति के गठिया, वीर्य वृद्धि, लकवा तथा वात दर्द में भी फायदेमंद होते हैं और मन को शांति का अहसास दिलाते हैं।

### काली एवं सफेद मूसली

अपने शरीर को स्वस्थ व बलिष्ठ बनाये रखने हेतू मुसली अति आवश्यक समझी जाती है। चिकित्सकों की राय में, मूसली की जड़ यौनवर्धक, वीर्यवर्धक तथा शक्तिवर्धक है जिससे व्यक्ति का शारीरिक कष्ट भी छूमंतर हो जाता है। इसलिए इस अनोखे पौधे के गुणों-अवगुणों की सटीक जानकारी रखनी चाहिए, तभी आप स्वयं को स्वस्थ कर पायेंगे, वरना क़तई नहीं।

### मुलहठी

हर्बल पौधों में मुलहठी की जड़ को सर्दी, खांसी, जुकाम, अल्सर जैसे रोगों के शमन हेतू अक्सर उपयोग में लाया जाता है जिससे इस समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी आराम मिलता है। यदि आप भी उपरोक्त रोगों से चिंतित हैं तो समाधान के लिए इसकी जानकारी लेकर ख़ूब इस्तेमाल कर सकते हैं। नि:संदेह यह आपको चिन्तामुक्त कर देगी।

### अजवायन

मसाले के रूप में मौजूद अजवायन रूपी अनमोल औषधीय पौधा शरीर में उत्पन्न होने वाले कब्ज़, कफ, पेट दर्द, वायुगोला, सूखी खांसी, हैजा, अस्थमा तथा पथरी आदि अधिकांश रोगोपचार में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इन सभी रोगों से छुटकारा पाने हेतू आप अजवायन के पौधे की विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हुए इसकी पत्ती, तना एवं फूल को उपयोग में ला सकते हैं। ❑❑

## शेष.... प्रथम पृष्ठ

चोट कर रही है जहां- जहां ममता को दुखे भी और चुभे भी। केजरीवाल की चोट का भाजपा के पास फिलहाल कोई इलाज नहीं दिख रहा है। ममता चाहे तो चोट की दर्द भूलकर उल्टे भाजपा के वोट बैंक पर केजरीवाल की तरह सेंध लगाने का काम कर सकती हैं लेकिन, फिलहाल वह जांच एजेंसियों से मिले दुखड़े सुनाने, भुनाने में लगी हैं, जिसमें जनता के दुख शामिल नहीं हैं। यह बात ममता बनर्जी जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा होगा।❑❑

## शेष.... जनगणना की जटिल राह...

जाने वाले जन और जनगणना करने वाले लोग स्थानीय हैं। गांव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी तुरंत पूरे गांव में फैल जाती है, अत: इस जानकारी को अविलंब पंजी में दर्ज किया जा सकेगा।

इस तरह से सभी विकास खंडों के आंकड़ों की गणना कर जिले की जनगणना प्रत्येक माह होती रहेगी। जिलावार जनगणना के डाटा को प्रदेश स्तर पर सांख्यिकीय कार्यालय में इकट्ठा कर प्रदेश की जनगणना का आंकड़ा भी प्रत्येक माह सामने आता रहेगा। प्रदेश वार जनसंख्या के आंकड़ों को देश की राजधानी में जनसंख्या कार्यालय में संग्रहित कर हर माह देश की जनगणना का वैज्ञानिक व प्रामाणिक आंकड़ा मिलता रहेगा। देश के नगर व महानगर वार्डों में विभक्त है, इसलिए वार्ड वार जनगणना के लिए गिनती की उपरोक्त प्रणाली ही अपनाई जाए। इस गिनती में जितनी पारदर्शिता और शुद्धता रहेगी, उतनी किसी अन्य पद्धति से संभव नहीं है।❑❑

## शेष.... नगर निगम चुनाव....

ज़िम्मे होता है एक चिट्ठी का बहाना लेकर चुनाव रद्द करना और सुप्रीम कोर्ट जाना महज़ दिखावा है। 'आप' घड़ियाली आंसू बहा रही है। बीते 15 सालों से भाजपा एमसीडी में और सात साल से 'आप' सरकार पर काबिज है दिल्ली की हालत खराब है और आए दिन कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं।' भाजपा तीनों निगमों के एकीकरण को कामकाज के लिए अनिवार्य मानती है। कपूर कहते हैं कि एकीकरण से सीमा विवाद ख़त्म होगा, ख़ासतौर पर उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों की सीमा पर रहने वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई तरह के शुल्क तीनों नगर निगमों में अलग-अलग हैं जो एकीकरण के समान हो जाएंगे। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता कपूर कहते हैं, एकीकरण से मेयर नामक संस्था का सम्मान लौटेगा, जो तीन मेयर होने से बिखर गया था।

उद्देश्य साफ है। भाजपा केजरीवाल को सीधी टक्कर देने के इरादे से गोटियां फिट कर रही है। एक ताक़तवर मेयर इसी दिशा में एक क़दम हो सकता है। निगम एकीकरण विधेयक इसी बजट सत्र में आ चुका है, पर असली प्रश्न यह है कि नगर निगम चुनाव कब होगा?❑❑

## शेष.... क्रिकेट खेलतीं...

पहले हम सिर्फ झाड़ू और मोगरी पकड़ते रहते थे, लेकिन अब हमारे हाथ में बल्ला है। इसी तरह की ढेगी गांव की मधु कहती है कि फाइनल खेलने के लिए हम सब रोज़ मैदान में प्रेक्टिस करती हैं। हमें प्रोत्साहन देने के लिए परिजनों ने घर के कामों को आपस में बाट लिया हैं वे हमें घर के काम से मुक्त रखते हैं, जिससे हम क्रिकेट खेल सकें। यही सबसे बड़ा बदलाव है। क्रिकेट के ज़रिये समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव संभव हो पा रहा है। ख़ासकर लड़कियों को देखने का नजरिया बदल रहा। इन लड़कियों ने दिखा दिया कि लड़कियां भी बखूबी क्रिकेट खेल सकती हैं। अब यहां की लड़कियां खेल में ही कैरियर बनाना चाहती हैं।❑❑

## शेष.... मंज़र पस-मंज़र

प्रदेश में गाज़ियाबाद की सीमा तक आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच सकता है। मेट्रो स्टेशन से बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस हाल्ट स्टेशन में विशेष बात यह भी है कि पहली बार मेट्रो ने पूर्व निर्मित स्टील के ढांचे से हाल्ट इंटरचेंज स्टेशन तैयार किया है। डीएमआरसी चौथे चरण के तीन कॉरिडोर पर 12 इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण करेगा, जिनमें से नौ नए स्टेशन होंगे, जबकि तीन पुराने स्टेशनों को इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। इससे मेट्रो में 37 इंटरचेंज स्टेशन उपलब्ध हो जाएंगे, जो मेट्रो यात्रियों के लिए ख़ासे सुविधाजनक साबित होंगे। इससे यात्री अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़कर दिल्ली के किसी भी कोने तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे उन्हें सड़क मार्ग का इस्तेमाल कम करने या नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे यातायात जाम में समय बर्बाद नहीं होगा और जाम में फंसने से होने वाली मानसिक परेशानी से भी वे मुक्त रहेंगे। लोगों को चाहिए कि वे मेट्रो का आधिकारिक उपयोग करें, ताकि वे सुरक्षित तेज और सुविधाजनक सफर कर सकें और सड़कों पर वाहनों का दबाव भी कम हो सके। साथ ही मैट्रो प्रबंधन को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेट्रो में तकनीकी खामी न आने पाए।❑❑

# कोरोना के नए 'एक्सई' वैरिएंट की देश में दस्तक

देश में 6अप्रैल को कोविड-19 के 'एक्सई' वैरिएंट का पहला मामला सामने आया। मायानगरी मुंबई में नए वैरिएंट का पहला मामला सामने आने के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं और लोग इस वैरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले सप्ताह एक नए म्यूटेंट के खिलाफ चेतावनी जारी की थी, जो पहले देखे गए कोविड-19 के किसी भी स्ट्रेन से अधिक संक्रमणीय हो सकता है। एक्सई वैरिएंट ओमिक्रॉन वैरिएंट के उपभेदों का एक उत्परिवर्तन है, जो दुनिया भर में फैला हुआ है। इसके बारे में पहली बार 19 जनवरी को यूके में पता चला था और तब से सैकड़ों रिपोर्ट और पुष्टि की जा चुकी है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह अन्य ओमिक्रॉन म्यूटेशन की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक तेजी से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, नया एक्सई वैरिएंट दो अन्य ओमिक्रॉन वैरिएंट्स, बीए.1 और बीए.2 का एक म्यूटेंट हाईब्रिड है और वैश्विक स्तर पर फैल रहे मामलों के लिए जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि नया म्यूटेंट ओमिक्रॉन के बीए.2 सब-वैरिएंट की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक ट्रांसमिसिबल (तेजी से फैलने वाला) है। हालांकि दुनिया भर में एक्सई के फिलहाल कम ही मामले देखने को मिले हैं, मगर इसकी अत्यधिक उच्च संचरण क्षमता का मतलब यह हो सकता है कि यह निकट भविष्य में सबसे प्रभावशाली स्ट्रेन बन जाता है।

## शेष.... दिल्ली में क़दम जमाने के बाद...

दुहते रह गए, चमकौर साहिब से एक डाक्टर व भदौड़ से मोबाइल रिपेयर करने वाला, जिसकी मां स्कूल में सफाई सेविका है, चन्नी को बुरी तरह हरा कर ये गया, वह गया। सुखबीर बादल के अपने हलके जलालाबाद में कराए विकास के गुमान को पहली बार चुनाव में उतरे गोल्डी कंबोज ने बड़े अंतर से हरा कर राजनीति की दिशा व दशा ही बदल दी। बड़े बादल साहब का अजेय क़िला भी धूल-धूसरित हो गया। कैप्टन की आयु के आख़िर पड़ाव में चुनाव लड़ने की चाह ने रजवाड़ाशाही की नींव हिला दी। सिद्धू व मजीठिया की अहं की लड़ाई ने जीत का बटन आम आदमी को बहन को पकड़ा दिया। भाजपा के भी तो अंतत: प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा व जंगी लाल महाजन कार्यकर्ता ही जीते। पंजाब में भाजपा का देर से उतरना 'आम आदमी पार्टी' के एकछत्र वर्चस्व कायम करने व राजनीतिक ऑक्सीजन देने का काम कर, उनके पक्ष को पंजाबियों की स्वाभाविक पसंद बना गया। चाहे परिस्थितियों वश ही सही, भाजपा की देर 'आम आदमी पार्टी' के लिए सवेर बन गई क्योंकि दूसरी कोई पसंद थी ही नहीं। परंपरागत पार्टियों में अब गहन व सूक्ष्म विश्लेषणों के नाम पर कईयों की बलि का बकरा बनाया जाएगा। सच्चाई को दरकिनार कर अपना दामन 'दोषमुक्त साबित करने के लिए' तिकडमबाजियां की जाएंगी। आंकड़ों के बल पर वोट प्रतिशत गिनाया जाएगा। अगले चुनाव में गलतियों को सुधार कर, चाहे ऊपरी तौर पर ही सही, बड़ी जीत का संकल्प दोहराया जाएगा। पराजय के तकरीकी कारण गिनाकर आम कार्यकर्ता को फिर से मूर्ख बनाया जाएगा।?

कोई पूछे तो कौन सी तकनीकी विशेषता थी जिसने 'आम आदमी पार्टी' को इतने बड़े अंतर से जिता दिया। न उनके बूथों पर भीड़ थी, न इन परपंरागत दलों जैसा उनके पास ढांचा था, लोगों ने खुद उनका चुनाव लड़ा व चुनाव को जनांदोलन बना दिया। पंजाबियों ने जैसे सरल राजनीति को अधिमान दिया, स्थापित दलों को भी यही करना होगा, जटिलता से सरलता की ओर आना होगा।❑❑

## शेष.... सत्य आयोग बनाओ....

ज़रा सोचिए, उन्होंने जो बजट पेश किया, हमारे राज्य का बजट, उसमें 80 प्रतिशत सुरक्षा के लिए दिया और 20 प्रतिशत विकास के लिए 20 प्रतिशत से आप कितने विकास की उम्मीद कर सकते हैं और उन लोगों के लिए जो देश के साथ खड़े हैं?

**सवाल:**- आपकी राय में अनुच्छेद 370 ख़त्म करने का असर क्या रहा है?

**जवाब:**- उन्होंने कहा कि इन त्रासदियों के पीछे अनुच्छेद 370 है और एक बार यह ख़त्म हो गया तो आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। मैं भारत सरकार से और गृहमंत्री से, जिन्होंने यह ऐलान किया था, पूछना चाहता हूं, क्या उग्रवाद चला गया? क्या अब लोग नहीं मर रहे हैं? क्या कहीं कोई बम नहीं चल रहे हैं? ये चीज़ें अब भी हो रही हैं और उग्रवादी केवल पाकिस्तान से ही नहीं आ रहे हैं। वे यहां से हमारे लोगों (के बीच) से भी है। वह क्या है जो उनसे यह सब करवा रहा है? वे इतने अलग थलग क्यों महसूस कर रहे हैं कि अपनी जान तक देने पर तुले हैं? वक्त आ गया है कि हमें वजह खोजकर उसका इलाज करना चाहिए, बजाए इसके कि इसे तब तक घिसटने दें, जब तक कि यह इतना खतरनाक बन जाए कि किसी को पता न हो कि अंजाम क्या होगा।

**सवाल:**—प्रधानमंत्री कश्मीरी नेताओं से मिले, जिनमें आप भी थे, क्या उसके बाद चीज़ें बदली हैं?

**जवाब:**- मैंने तब प्रधानमंत्री से साफ कहा कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है और आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं हे, तो आइए वह भरोसा पैदा करने की कोशिश करें जो हमारे देश के भविष्य का निर्माण करेगा, उन्होंने अपने भाषण में हमसे वादा किया कि वे इस 'दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी' को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मगर उस दिशा में कुछ हुआ नहीं। बात विकास की नहीं है, बात कुछ नहीं है कि आप सोना भेजते हैं या चांदी। बात यह है कि आप दिलों के ज़ख़्म कैसे भरते हैं। सड़कें और पुल बनाकर दिलों के ज़ख़्म नहीं भरे नहीं जा सकते। उससे भी बढ़कर कुछ है : भरोसा। हमें एक दूसरे में भरोसे का निर्माण करना होगा, ताकि हम लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने के बजाए साथ जी सकें, साथ रह सकें, साथ आगे बढ़ सकें और साथ खुश रह सकें।

**सवाल:**— क्या इसमें विधान सभा चुनाव करवाना और राज्य का दर्जा बहाल करना भी शामिल है.?

**जवाब:**- हाँ, मैं समझता हूं कि यह पहला उदाहरण है, शायद पूरी दुनिया में, जहां जिस राज्य को देश का ताज होना था, उसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया, यही नहीं देखिए कि परिसीमन आयोग ने हमारी सीटें किस तरह बांटी है, वे भाजपा की सरकार थोपना चाहते हैं।

**सवाल:**— क्या आप यह कह रहे हैं कि भाजपा जेएंडके में हुकूमत करने के लिए हिन्दू मुख्यमंत्री लाना चाहती है?

**जवाब:**- वे कुछ भी कर सकते हैं। यह प्रयोग भी उन्हें आज़मा लेने दीजिए, वे जम्मू-कश्मीर को ऐसे हाथों में धकेल रहे हैं कि भगवान ही मदद करे।

**सवाल:**- क्या आप राज्य में हिन्दू मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे?

**जवाब:**- अगर ईमानदार परिसीमन और चुनाव हों, तो मेरे यह मायने नहीं रखता कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि उसे लोगों ने चुना होगा। वह उन पर थोपा नहीं गया होगा। हाल में महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए केन्द्रीय मंत्री कोटवाल कठुआ आए। मैं उनसे पूछना चाहता था कि महाराजा गुलाब सिंह का राज्य कहां है, अगर वह मौजूद नहीं है तो इस राज्य में प्रवेश बिन्दु पर उनकी मूर्ति क्यों लगा रहे हैं? मेहरबानी करके इस राज्य के लोगों और बाकी देश के लोगों के सामने यह स्पष्ट कीजिए।

**सवाल:**- आख़िर में, आपकी राय में कश्मीरी पंडितों की समस्याओं के अंत के लिए किस क़िस्म के समाधान की ज़रूरत है?

**जवाब:**- आगे का रास्ता यही है कि लोगों के दिल जीतें। एक भी कश्मीरी मुसलमान आप से यह नहीं कहेगा कि वह कश्मीर में हिन्दुओं को लौटते देखना नहीं चाहता, मगर क्या यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के वापस लौटने को बढ़ावा देगी? यही मेरा प्रश्न है उनसे।❑❑

**SHANTI MISSION** (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **3 April 2022** Posting Days : **MON-TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र — मीम.सीन.जीम

# •सेवा और मेवा •बढ़ता मर्ज़ •राहत की बात

## सेवा और मेवा

हर राजनेता जब चुनाव मैदान में उतरता है, तो लोगों से सेवा का मौक़ा मांगता है मगर चुनाव जीत जाने के बाद वह सेवा करे न करे, जीवन भर सेवा ज़रूर खाता रहता है। बेशक कोई चुनाव जीत कर दो दिन के लिए सदन में चला जाए, फिर कभी चुनाव लड़े या जीते, आजीवन उसे पेंशन और कई सुविधाएं मिलती रहती हैं। अगर कोई नेता कई बार चुनाव जीत चुका है, तो उसी के मुताबिक उसकी पेंशन की राशि प्रति कार्यकाल के हिसाब से बढ़ती जाती है। इस तरह कई नेता

**पिछले कुछ समय से पेंशन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई थी। तब से इसे दोबारा लागू करने की मांग उठती रही हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के समय जब तमाम राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाओं के लोकलुभावन वादे कर रहे थे, तब सपा ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर दिया।**

पांच लाख रुपए प्रति माह से अधिक की पेंशन पाते हैं। पंजाब की नई सरकार ने इस पर रोक लगा दी हैं अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल की पेंशन मिला करेगी जो फिलहाल पचहत्तर हज़ार एक सौ पचास रूपए मिलती है। स्वभाविक ही पंजाब सरकार के इस फैसले का आम जन में चौतरफा स्वागत हो रहा है। अपेक्षा की जा रही है कि दूसरी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार भी इस फैसले को नज़ीर मानते हुए कोई व्यावहारिक क़दम उठाएंगी। पंजाब सरकार ने यह फैसला राज्य का वित्तीय संकट दूर करने के मक़सद से किया है। देश के तमाम राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, इसलिए उनसे भी ऐसे फैसले की उम्मीद की जा रही है।

पिछले कुछ समय से पेंशन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई थी। तब से इसे दोबारा लागू करने की मांग उठती रही हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के समय जब तमाम राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाओं के लोकलुभावन वादे कर रहे थे, तब सपा ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर दिया। उस वायदे को लपकते हुए आगमी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अपने यहां पुरानी पेंशन योजना लागू भी कर दी। तब यह प्रश्न जोर शोर से उठने लगा कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन बंद नहीं की जाती, तो केवल सरकारी कर्मचारियों को यह सज़ा क्यों दी जा रही है। आख़िर अवकाश प्राप्ति के बाद उन कर्मचारियों को भी अपना परिवार चलाना होता है। यह कहां का सामाजिक न्याय है। इस दृष्टि से भी पंजाब सरकार के ताज़ा फैसले से लोग खुश हैं। हालांकि पंजाब से पहले हरियाणा सरकार ने विधायकों की पेंशन राशि सीमा एक लाख रुपए तक सीमित कर रखी है। पर वह फैसला केवल दो हज़ार चौदह के बाद के विधायकों पर लागू है। इस तरह वहां करीब ढाई सौ विधायक पुराने नियम के तहत लाखों रुपये की पेंशन ले रहे हैं।

विधायकों और सांसदों की पेंशन इसलिए भी लोगों को खटकती रही है कि चुनाव जीतने के बाद ज़्यादातर नेताओं की संपत्ति एकदम से कई गुना बढ़ जाती है। चुनाव जीतते ही वे रातोंरात अमीर हो जाते हैं। उसके बावजूद उन्हें लाखों रुपए पेंशन मिलती है। कई तो सांसद और विधायक दोनों की पेंशन लेते हैं। फिर उन्हें चिकित्सा यात्रा आदि के मत में भत्ते और सुविधाएं मिलती रहती हैं। इससे राज्य सरकारों पर भारी वितीय बोझ पड़ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री का यह तर्क उचित है कि जब राजनेता सेवा के मक़सद से राजनीति में आते हैं, तो उन्हें पेंशन की फिक्र क्यों होना चाहिए। पंजाब ने एक नज़ीर पेश कर दी है, अब दूसरे राज्यों की ओर नज़र हैं।

## बढ़ता मर्ज़

भारत में तपेदिक यानि टी.बी. की ताज़ा स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय की पिछले जारी जो रिपोर्ट आई, वह चौंकाने वाली है। रिपोर्ट बताती चौंकाने वाली है। रिपोर्ट बता रही है कि वर्ष 2021 में 2020 के मुक़ाबले टीबी के मरीज़ों की संख्या उन्नीस प्रतिशत बढ़ गई। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह रही कि 2019 से 2020 के बीच टीबी से मरने वालों की संख्या में 11 प्रतिशत का इज़ाफा देखा गया। ऐसा नहीं कि टीबी के मामलों में उछाल पिछले वर्ष ही आया, वर्ष 2019 में भी टीबी मरीज़ों की संख्या ग्यारह प्रतिशत बढ़ गई थी। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि देश में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम कहीं न कहीं अपने लक्ष्य में पिछड़ता जा रहा हैं गौरतलब यह भी है कि पिछले एक दशक में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इलाज करवाने वालों की संख्या छह-सात फीसद से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई हैं ऐसे में यह प्रश्न उठना लाज़िमी है कि सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है, वह कैसे हासिल हो पाएगा? प्रश्न यह भी कि व्यापक स्तर पर चल रहे तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम में आख़िर ऐसी क्या ख़ामिया हैं जिनकी वजह से इसका दायरा नहीं बढ़ पा रहा है। टीबी जानलेवा संक्रामक बीमारी है। हर वर्ष इसके लाखों नए मरीज़ सामने आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी पांच लाख सालाना से कम नहीं दिख रही। इसका मतलब साफ है कि टीबी को लेकर न तो लोगों में जागरुकता है, न ही सरकारों के प्रयासों में गंभीरता। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी चौसठ प्रतिशत टीबी मरीज़ इलाज नहीं करवाते। टीवी को लेकर करवाए गए सर्वे बताते हैं कि 18 प्रतिशत लोगों को भी यह नहीं पता कि इस बीमारी के लक्षण क्या है? अगर जागरुकता का अभाव न हो तो ऐसे लोग समय पर इलाज करवा कर अपने को बचा सकते हैं। पिछले दिनों आए राष्ट्रीय टीबी व्यापकता सर्वे के नतीजों से साफ पता चलता है कि टीबी के लक्षण वाले 62 प्रतिशत लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं नहीं लीं। इतना ही नहीं, 12 प्रतिशत लोगों ने तो खुद ही अपना इलाज कर लिया। जबकि 02 प्रतिशत टीवी मरीज़ ऐसे थे जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि देश में टीबी से निपटने को लेकर हम कितने लापरवाह है।

संकट इसलिए भी गहराया है कि दो वर्ष से देश कोरोना महामारी झेल रहा था इस दौरान कोरोना संक्रमितों का इलाज ही प्राथमिकता में था। ऐसे में दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मरीज़ों की सुध कौन लेता? ज़ाहिर है इन दो सालों में टीवी के नए मरीज़ों का पंजीकरण भी नहीं हो पाया। इसलिए भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को धक्का लगना ही था। समस्या यह भी है कि जो लोग लक्षण पता चल जाने पर भी इलाज नहीं करवाते, वे दूसरों के लिए बड़ा ख़तरा बन जाते हैं। ज़ाहिर है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सरकारों को रणनीति ऐसी बनानी होगी जिससे कि हर मरीज़ तक पहुंच बने और उसे इलाज दिया जा सके। अगर लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवाते तो यह और गंभीर बात है। देश से टीवी का ख़ात्मा तभी हो पाएगा जब इससे निपटने के लिए हर स्तर पर काम हो, चिकित्सकर्मी उन बस्तियों और तबक़ों के कमी के कारण इलाज करवाने से कतराते हैं। वरना यह आंकड़ा तो बढ़ता ही जाएगा।

## राहत की बात

दिल्ली मैट्रो का पहला हाल्ट इंटरचेंज स्टेशन शुरू किया जाना स्वागतयोग्य है। ग्रीन लाइन (बहादुरगढ़ सिटी पार्क-इन्द्रलोक कीर्ति नगर) पर शुरू किए गए। पंजाबी बाग पश्चिम इंटरचेंज स्टेशन

**टीवी को लेकर करवाए गए सर्वे बताते हैं कि 18 प्रतिशत लोगों को भी यह नहीं पता कि इस बीमारी के लक्षण क्या है? अगर जागरुकता का अभाव न हो तो ऐसे लोग समय पर इलाज करवा कर अपने को बचा सकते हैं। पिछले दिनों आए राष्ट्रीय टीबी व्यापकता सर्वे के नतीजों से साफ पता चलता है कि टीबी के लक्षण वाले 62 प्रतिशत लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं नहीं लीं।**

से मैट्रो की यह लाइन अब पिंक लाइन (मजलिस पार्क-शिव विहार) के साथ जुड़ गई हैं ये दोनों कॉरिडोर इससे पूर्व एक-दूसरे से जुड़े नहीं थे। यानि अब हरियाणा के बहादुरगढ़ के साथ ही दिल्ली के मुंडका व आसपास के स्टेशनों से मेट्रो में सवार हुआ यात्री सरोजनीनगर, दिल्ली हाट, आएनए, लाजपत नगर और निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन होते हुए उत्तर

बाक़ी पेज 11 पर

**ज़रूरी ऐलान**
आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।
**रक़म भेजने के तरीक़े:-**
❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर
SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

**ख़रीदारी चन्दा**
वार्षिक Rs.130/-
6 महीने के लिए Rs.70/-
एक प्रति Rs.3/-
जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
**शांति मिशन**
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173